

जीवन में थोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना मां-बाप सीखा देते हैं लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है।

TODAY WEATHER



DAY NIGHT
41° 29°
Hi Low

संक्षेप

पीएम मोदी की योजनाएं 'विकसित भारत' का आधार, बदल रहा देश

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पिछले 12 वर्षों में विकास की एक नई धारा शुरू करने के लिए प्रशंसा की, जो सेवा, सुरक्षा और गरीबों के कल्याण पर केंद्रित है। धामी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट किया कि सरकार द्वारा 'अंत्योदय' के तहत प्रमुख केंद्रित करने से - समाज के सबसे कमजोर वर्गों का उत्थान करने पर - लाखों गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदर्शपूर्ण नेतृत्व में, पिछले 12 वर्षों में, सेवा, सुरक्षा और गरीबों के कल्याण को केंद्र में रखकर देश में विकास की एक नई धारा प्रवाहित हुई है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस कल्याणकारी दृष्टिकोण ने हरिण पर रहने वाले नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित रूप से ऊपर उठाया है। केंद्रीय कल्याणकारी पहलों के व्यापक प्रभाव को उजागर करने के लिए, धामी ने मोदी के कार्यकाल के दौरान लाए गए कई प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने जन धन खाते, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और पीएम आवास योजना जैसे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जन कल्याण योजनाओं ने गरीबों, वंचितों और समाज के सबसे निचले तबके में खड़े लोगों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के प्रति उत्तराखंड की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, धामी ने राज्य में दोहरा इंजन वाली सरकार की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया।

बिहार कोचिंग विवाद: रौशन आनंद की जमानत पर आदेश सुरक्षित, खान सर मामले में आज सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को जुड़िशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनुराग वर्मा की अदालत में प्रमुख कोचिंग संस्थानों से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद की रेगुलर जमानत अर्जी पर बहस पूरी हुई, जिसके बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। वहीं, खान सर के ग्लोबल इंस्टीट्यूट से जुड़े मामले में गिरफ्तार दो बॉडीगार्ड्स की जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच से जुड़े दस्तावेज और प्रोसेस रिपोर्ट पेश किए जाएं। सूत्रों के मुताबिक, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। रौशन आनंद ने रेगुलर जमानत की मांग की, जबकि अभियोग पक्ष ने मामला की गंभीरता को उजागर करते हुए अपना पक्ष रखा। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि फैसला बाद में सुनाया जाएगा। उधर, खान सर के दो बॉडीगार्ड्स के मामले में अदालत ने कहा कि जमानत अर्जी पर फैसला लेने से पहले जांच के तथ्यों की जांच करना जरूरी है। इसे देखते हुए पुलिस से केस डायरी पेश करने को कहा गया।

शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इंडिया गठबंधन की बैठक में खड़गो ने नीट समेत 5 मुद्दों पर सरकार को घेरा

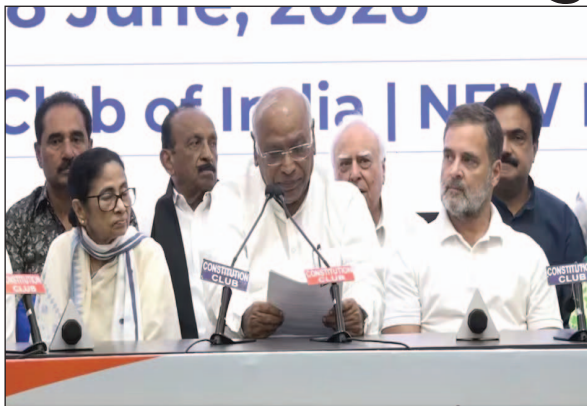
नई दिल्ली, एजेंसी। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की अहम बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हर 2 महीने में गठबंधन की बैठक बुलाई जाएगी। हमारी अगली बैठक हैदराबाद में बुलाई जाएगी। आज की अहम बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। इसके तहत SIR के मामले पर हम मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखेंगे। साथ ही हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। खरगे ने आज सोमवार को कहा कि बैठक में 5 मुद्दों पर आपसी सहमति बनी है। पहला, वोट लूट के खिलाफ चीफ जस्टिस को पत्र लिखा जाएगा। दूसरा, NEET-UG पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री (धर्मेश प्रधान) को तुरंत इस्तीफा लिया जाना चाहिए। तीसरा, आर्थिक हालत पर संवदलीय बैठक बुलाई जाए। चौथा, हर 2 महीने में हमारी बैठक होगी, इसकी अगली बैठक हैदराबाद में 8 अगस्त को होगी। पांचवां, संसद में सभी पार्टियों का कॉन्डिनेशन जारी रहेगा।

इंडिया गठबंधन की बैठक में इन पांच मुद्दों पर बनी सहमति

यह सहमति बनी कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनावों की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। यह पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए, यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग की जाए, क्योंकि उनके कार्यकाल में NEET और CBSE परीक्षाओं में शामिल लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है। वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों तथा जनसरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार को तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। यह तय हुआ कि सभी पार्टियां हर दो महीने में मिलेंगी। मानसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट को ऑर्डिनेशन जारी रहेगा और विपक्ष के नेता के ऑफिस में रोज सुबह मीटिंग होगी। खरगे ने कहा कि, "इस बात पर सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां हर दो महीने में मिलेंगी। अगली मीटिंग अगस्त में हैदराबाद में होगी।" खरगे ने कहा कि हमने 17 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में अपनी एकजुटता और एकता को बहुत निर्णायक तरीके से दिखाया, जब हम सबसे मजबूती से एकजुट होकर डिलिमिटेशन पर मोदी सरकार के दुर्भावनापूर्ण विलों को परास्त किया। अब हमें उसी भावना को और मजबूत करना है और आगे बढ़ना है, ताकि मोदी सरकार के कुशासन के कारण देश के सामने खड़ी कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके।

हैदराबाद में होगी इंडिया गठबंधन की अगली बैठक

खरगे ने कहा, "केंद्र सरकार को अभी की खराब आर्थिक हालत, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे और दूसरे लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। यह तय हुआ कि सभी पार्टियां हर दो महीने में मिलेंगी। मानसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट को ऑर्डिनेशन जारी रहेगा और विपक्ष के नेता के ऑफिस में रोज सुबह मीटिंग होगी।" खरगे ने कहा कि, "इस बात पर सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां हर दो महीने में मिलेंगी। अगली मीटिंग अगस्त में हैदराबाद में होगी।" खरगे ने कहा कि हमने 17 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में अपनी एकजुटता और एकता को बहुत निर्णायक तरीके से दिखाया, जब हम सबसे मजबूती से एकजुट होकर डिलिमिटेशन पर मोदी सरकार के दुर्भावनापूर्ण विलों को परास्त किया। अब हमें उसी भावना को और मजबूत करना है और आगे बढ़ना है, ताकि मोदी सरकार के कुशासन के कारण देश के सामने खड़ी कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके।



बैठक में शामिल हुई 25 पार्टियां

बैठक के बाद खरगे ने कहा, "इंडिया गठबंधन की बैठक में 25 पार्टियां शामिल हुईं। उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन भी वर्युअली मीटिंग में शामिल हुए और अपने विचार शेर किए। वे भी इन सभी मुद्दों पर सहमत हैं।" इसके बाद, हम पांच पॉइंट्स पर आम सहमति पर पहुंचे। हम आज सहमत हुए हैं, हम इन मुद्दों के लिए लड़ेंगे, उन पर काम करेंगे, और आगे बढ़ेंगे।" खरगे ने कहा, "SIR, वोट लूट और चुनाव में चोरी पर मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजने पर सहमति बनी। यह पत्र बहुत जल्द मुख्य न्यायाधीश को दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, शिक्षा मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग करने पर एकमत से सहमति बनी, क्योंकि उन्होंने NEET और CBSE एजाम देने वाले लाखों युवाओं के साथ धोखा किया।"

लिये केंद्र सरकार को तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। यह सहमति बनी कि INDIA जनबंधन के सभी दल प्रत्येक दो माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी।

'भर्ती एजेंसियों ने मनमाना रवैया अपनाया'

तेलंगाना पुलिस भर्ती केस पर 'सुप्रीम' टिप्पणी, अभ्यर्थी को मिली राहत

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना में पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के एक अभ्यर्थी की उम्मीदवारी बहाल करने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि राज्य की भर्ती एजेंसियों ने एक ऐसे आपराधिक मामले के आधार पर नियुक्ति से इनकार कर मनमाना रवैया अपनाया, जो एक असफल प्रेम संबंध से जुड़ा था और बाद में लोक अदालत में समझौते के जरिए समाप्त हो गया था।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में गजुल थिरुपति नाम के युवक ने याचिका दायर की थी। इसे मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवाजन बेंच के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें 'स्टाईपेंडरी केडेट ट्रेनिंग पुलिस कॉन्स्टेबल' (एससीटीपीसी) पद के लिए उनके अस्थायी चयन को रद्द किए जाने को सही ठहराया गया था। अपने फैसले में न्यायमूर्ति मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि नियुक्ति किसी आपराधिक मामले में बरी या मुक्त हो चुके उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा निर्णय मनमाना नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "राज्य और उसके अधिकारी मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकते। इसलिए, जब ऐसे फैसले की न्यायिक समीक्षा की जाती है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मनमाना न हो, तो यह दिखाया जाना चाहिए कि (क) रिकॉर्ड पर ऐसा सामग्री मौजूद हो जिससे यह संकेत मिले कि वास्तव में नैतिक अधमता वाला अपराध किया गया था और (ख) उम्मीदवार के खिलाफ ऐसा ठोस सामग्री हो, भले ही वह बरी या मुक्त हो गया हो।"



कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवाजन बेंच के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें 'स्टाईपेंडरी केडेट ट्रेनिंग पुलिस कॉन्स्टेबल' (एससीटीपीसी) पद के लिए उनके अस्थायी चयन को रद्द किए जाने को सही ठहराया गया था। अपने फैसले में न्यायमूर्ति मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि नियुक्ति किसी आपराधिक

इंडिया ब्लॉसिर्फ कमियां छिपाने का माध्यम: चिराग पासवान का बड़ा हमला, कहा- 'सत्ता के लिए समझौता'

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (आरवी) के प्रमुख चिराग पासवान ने सोमवार को कांग्रेस के साथ मतभेदों के बावजूद तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों और अन्य कई दलों की इंडिया ब्लॉक की बैठक में उपस्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि गठबंधन एक-दूसरे की कमियों को छिपाने का माध्यम है। पत्रकारों से बात करते हुए पासवान ने कहा कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बैठक में शामिल होने पर उन्हें आश्चर्य हुआ है। चिराग ने पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा ममता बनर्जी की अलाउचन का जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए अपने सहयोगी द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम



को धोखा दिया और इंडिया ब्लॉक में कथित दरारें यह दर्शाती हैं कि एसी बैठकों का कोई अर्थ नहीं है। पासवान ने कहा कि इंडी गठबंधन में जिस तरह की दरारें दिख रही हैं, कांग्रेस द्वारा सत्ता के लिए अपने सहयोगी को धोखा देने के बाद डीएमके का नाराज होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि मुझे ममता जी पर आश्चर्य है, जो राहुल गांधी द्वारा बंगाल चुनाव के दौरान उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के बावजूद बैठक में भाग लेने के लिए एक दिन पहले ही आ गई हैं। यह दर्शाता है कि यह गठबंधन एक समझौता है, एक-दूसरे

इंडिया ब्लॉक की एकजुटता ही मोदी के सामने जीत का मंत्र

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता शरद पवार ने 8 जून को आयोजित इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान विपक्षी दलों के बीच एकता के महत्व पर जोर दिया। महाराष्ट्र के बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व के जवाब में विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रीय पार्टियां एकजुट होने लगी हैं। भाजपा और उसका प्रशासन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है। दूसरी ओर, जो लोग इस नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते, वे भी एकजुट हो गए हैं। हम प्रमुख हरितियों को आमंत्रित करेंगे और आगे का रास्ता निकालेंगे। मुझे विश्वास है कि कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज की बैठक में एक फॉर्मूला प्रस्तावित किया जाएगा, जिसमें यह सुझाव दिया जाएगा कि किसी को भी अपने रुख में अत्यधिक कठोरता नहीं दिखानी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए सुषिखा सुले इस बैठक में शामिल रही हैं। इसके बाद हम दिल्ली में बैठकर आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे। अगले दो-तीन वर्षों तक कोई चुनाव निर्धारित नहीं है। ऐसे समय में सभी को एकजुट रखना बेहद जरूरी है।



SIR पर एकजुट हुई पार्टियां

उन्होंने कहा कि SIR के कारण हमारे करोड़ों लोगों से उनका मताधिकार छीना जा रहा है। संविधान पर हमला लगातार जारी है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और डराने-धमकाने के औजार के रूप में लगातार किया जा रहा है। गैर-BJP सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जरूरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आर्थिक माहौल बेहद नकारात्मक है। नई नौकरियों पैदा करने के लिए जिस रफ्तार से नए निवेश आने चाहिए, वे बिल्कुल उस रफ्तार से नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में निजी एकाधिकार बढ़ रहा है और MSMEs का भविष्य गंभीर संकट में है। परीक्षा प्रणाली के पूर्ण कुप्रबंधन के कारण हमारे लाखों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार, खासकर BJP शासित राज्यों में, लगातार जारी है। हमारी विदेश नीति के साथ पूरी तरह से समझौता किया गया है और उन पारंपरिक मूल्यों को कायम नहीं रखा गया है, जिनकी भारत लंबे समय से पुरजोर समर्थन करता रहा है।

राम मंदिर ट्रस्ट का अखिलेश यादव को जवाब, कहा- दान का हिसाब-किताब पूरी तरह पारदर्शी

नई दिल्ली, एजेंसी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें मंदिर के दान में करोड़ों रुपये गायब होने की बात कही गई थी। ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेन्द्र दास महाराज ने कहा कि सभी लेन-देन विधिवत दर्ज किए जाते हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ संसाधित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और लिखित रूप में दर्ज किए जाते हैं। सभी लेन-देन का हिसाब-किताब सावधानीपूर्वक रखा जाता है, और सब कुछ सही और पारदर्शी तरीके से चल रहा है। दिनेन्द्र दास महाराज ने कहा कि आपसी सद्भाव और प्रेम है। राम जी



सब कुछ देख रहे हैं। लोग चाहे जो कहें, लेकिन राम लखला से संबंधित कार्य पूरी तरह से सुचारु रूप से चल रहा है। उन्होंने आगे कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रस्ट कभी ऐसी

गलती नहीं करेगा। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है और अब तक कोई उल्लेखनीय अनियमितता नहीं पाई गई

है।

राय ने एक बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है, जो ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। वर्तमान में भी यही प्रक्रिया जारी है। अब तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। अपने पोस्ट में यादव ने केंद्र सरकार की संदिग्ध चुप्पी पर भी प्रकाश डाला और सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि यह मामला वैश्विक स्तर पर संपूर्ण सनातन समुदाय की भगवान राम में गहरी आस्था से सीधा जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है।

नहीं करेगा। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है और अब तक कोई उल्लेखनीय अनियमितता नहीं पाई गई

है।

राय ने एक बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है, जो ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। वर्तमान में भी यही प्रक्रिया जारी है। अब तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। अपने पोस्ट में यादव ने केंद्र सरकार की संदिग्ध चुप्पी पर भी प्रकाश डाला और सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि यह मामला वैश्विक स्तर पर संपूर्ण सनातन समुदाय की भगवान राम में गहरी आस्था से सीधा जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है।

नहीं करेगा। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है और अब तक कोई उल्लेखनीय अनियमितता नहीं पाई गई

है।

राय ने एक बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है, जो ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। वर्तमान में भी यही प्रक्रिया जारी है। अब तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। अपने पोस्ट में यादव ने केंद्र सरकार की संदिग्ध चुप्पी पर भी प्रकाश डाला और सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि यह मामला वैश्विक स्तर पर संपूर्ण सनातन समुदाय की भगवान राम में गहरी आस्था से सीधा जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है।

नहीं करेगा। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है और अब तक कोई उल्लेखनीय अनियमितता नहीं पाई गई

है।

राय ने एक बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है, जो ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। वर्तमान में भी यही प्रक्रिया जारी है। अब तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। अपने पोस्ट में यादव ने केंद्र सरकार की संदिग्ध चुप्पी पर भी प्रकाश डाला और सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि यह मामला वैश्विक स्तर पर संपूर्ण सनातन समुदाय की भगवान राम में गहरी आस्था से सीधा जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है।

नहीं करेगा। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है और अब तक कोई उल्लेखनीय अनियमितता नहीं पाई गई

है।

राय ने एक बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है, जो ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। वर्तमान में भी यही प्रक्रिया जारी है। अब तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। अपने पोस्ट में यादव ने केंद्र सरकार की संदिग्ध चुप्पी पर भी प्रकाश डाला और सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि यह मामला वैश्विक स्तर पर संपूर्ण सनातन समुदाय की भगवान राम में गहरी आस्था से सीधा जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है।

नहीं करेगा। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है और अब तक कोई उल्लेखनीय अनियमितता नहीं पाई गई

है।

राय ने एक बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है, जो ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। वर्तमान में भी यही प्रक्रिया जारी है। अब तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। अपने पोस्ट में यादव ने केंद्र सरकार की संदिग्ध चुप्पी पर भी प्रकाश डाला और सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि यह मामला वैश्विक स्तर पर संपूर्ण सनातन समुदाय की भगवान राम में गहरी आस्था से सीधा जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है।

नहीं करेगा। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है और अब तक कोई उल्लेखनीय अनियमितता नहीं पाई गई

है।

राय ने एक बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है, जो ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। वर्तमान में भी यही प्रक्रिया जारी है। अब तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। अपने पोस्ट में यादव ने केंद्र सरकार की संदिग्ध चुप्पी पर भी प्रकाश डाला और सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि यह मामला वैश्विक स्तर पर संपूर्ण सनातन समुदाय की भगवान राम में गहरी आस्था से सीधा जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है।

नहीं करेगा। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है और अब तक कोई उल्लेखनीय अनियमितता नहीं पाई गई

है।

राय ने एक बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है, जो ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। वर्तमान में भी यही प्रक्रिया जारी है। अब तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। अपने पोस्ट में यादव ने केंद्र सरकार की संदिग्ध चुप्पी पर भी प्रकाश डाला और सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि यह मामला वैश्विक स्तर पर संपूर्ण सनातन समुदाय की भगवान राम में गहरी आस्था से सीधा जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है।

12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव, केंद्र में गरीब और वंचित वर्ग का कल्याण: पीएम



नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूरे होने पर अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और नीतियों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट साझा की। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में भारत में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इन सभी के केंद्र में गरीब और वंचित वर्ग का कल्याण रहा है। पीएम मोदी ने लिखा कि पिछले 12 सालों में भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीबों और वंचितों का कल्याण रहा है। हम हमेशा 'अंत्योदय' से प्रेरित रहे हैं और हमारी कोशिश यही रही है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो दशकों से पीछे छूट गए थे। जनधन खातों और डायरेक्ट बेंचिफिट ट्रांसफर से लेकर स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जलजीवन मिशन, आयुष्मान भारत और अन्य योजनाओं तक हर पहल का मकसद बस यही रहा है कि लोगों को सम्मान और अवसर मिलें।

गरीबों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी ने अहम भूमिका निभाई

पीएम ने आगे लिखा कि यह भी खुशी की बात है कि गरीबों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में

टेक्नोलॉजी ने अहम भूमिका निभाई है। डायरेक्ट बेंचिफिट ट्रांसफर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक मदद सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। इससे कार्यक्षमता बढ़ी है और शासन-व्यवस्था में भरोसा मजबूत हुआ है। इस तरह, गरीब कल्याण को आगे बढ़ाने का सफर मानवीय सशक्तिकरण और 'विकसित भारत' के हमारे सपने को साकार करने की दिशा में एक सामूहिक आंदोलन बन गया है।

अमित शाह ने एक्स पर लिखा

वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि गरीब कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने '12 साल गरीब कल्याण' में अन्न योजना, पीएम आवास, जनधन, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग सुविधा, वित्तीय सुरक्षा और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर के जरिए देश के गरीबों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़कर 'विकसित भारत' को मजबूत नींव का निर्माण किया जा रहा है।

नेपाल बॉर्डर के पास से टीएमसी नेता जहांगीर खान गिरफ्तार

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त को एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने कई दिनों से फरार चल रहे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कद्दावर नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, खान को भारत-नेपाल सीमा (नेपाल बॉर्डर) के पास एक इलाके से आज सुबह तड़के पकड़ा गया।

खुफिया जानकारी के आधार पर एंटीटैरिफ काफ़ी समय से उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए थे। पुलिस प्रशासन के मुताबिक, जहांगीर खान के खिलाफ पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा पुलिस स्टेशन में सात अलग-अलग एफआईआर (FIR) दर्ज हैं। उन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से कुछ का हिसाब-किताब सावधानीपूर्वक रखा जाता है, और सब कुछ सही और पारदर्शी तरीके से चल रहा है। दिनेन्द्र दास महाराज ने कहा कि आपसी सद्भाव और प्रेम है। राम जी

नेपाल बॉर्डर के पास से टीएमसी नेता जहांगीर खान गिरफ्तार

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त को एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने कई दिनों से फरार चल रहे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कद्दावर नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, खान को भारत-नेपाल सीमा (नेपाल बॉर्डर) के पास एक इलाके से आज सुबह तड़के पकड़ा गया।

खुफिया जानकारी के आधार पर एंटीटैरिफ काफ़ी समय से उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए थे। पुलिस प्रशासन के मुताबिक, जहांगीर खान के खिलाफ पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा पुलिस स्टेशन में सात अलग-अलग एफआईआर (FIR) दर्ज हैं। उन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से कुछ का हिसाब-किताब सावधानीपूर्वक रखा जाता है, और सब कुछ सही और पारदर्शी तरीके से चल रहा है। दिनेन्द्र दास महाराज ने कहा कि आपसी सद्भाव और प्रेम है। राम जी

नेपाल बॉर्डर के पास से टीएमसी नेता जहांगीर खान गिरफ्तार

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त को एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने कई दिनों से फरार चल रहे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कद्दावर नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, खान को भारत-नेपाल सीमा (नेपाल बॉर्डर) के पास एक इलाके से आज सुबह तड़के पकड़ा गया।

खुफिया जानकारी के आधार पर एंटीटैरिफ काफ़ी समय से उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए थे। पुलिस प्रशासन के मुताबिक, जहांगीर खान के खिलाफ पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा पुलिस स्टेशन में सात अलग-अलग एफआईआर (FIR) दर्ज हैं। उन पर कई गंभीर आपरा

अखिलेश की हर बात का जवाब देना उचित नहीं, जालौन में बोले यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी

आर्यावर्त संवाददाता

जालौन। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जालौन के कोच में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से बड़ी जीत 2027 में हासिल करनी है, इसीलिए सभी कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं। साथ ही उन्होंने पंचायत चुनाव, राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की हर बात का जवाब देना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का कार्य है, राम मंदिर से किसी प्रकार का चढ़ावा चोरी नहीं हुआ है और नीट मामले में



सरकार ने जांच समिति गठित कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं संगठन को मजबूत करने का आह्वान

पार्टी के राष्ट्रीय और वरिष्ठ नेतृत्व के आभारी

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि वह पार्टी के राष्ट्रीय और वरिष्ठ नेतृत्व के आभारी हैं, जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा कार्यकर्ताओं की बदौलत आगे बढ़ी है और उनकी हर चुनावी जीत के पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण रहा है।

बीजेपी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता

उन्होंने कहा कि बीजेपी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता हैं।

कार्यकर्ता मजबूत होगा तो संगठन और पार्टी भी मजबूत होगी। साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने की जिम्मेदारी भी कार्यकर्ताओं के कंधों पर है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं को आज भी एक कार्यकर्ता मानते हैं और वर्ष 1991 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी यह भ्रम नहीं रहा कि उन्होंने अपने दम पर चुनाव जीते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी एक संगठनात्मक और अनुशासित पार्टी है। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। जब तक जनता को योजनाओं की जानकारी नहीं होगी, तब तक विकास

कार्यों का वास्तविक लाभ समाज तक नहीं पहुंच पाएगा।

आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने की सलाह

उन्होंने कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने की सलाह देते हुए कहा कि व्यक्तिगत खींचतान से संगठन को नुकसान पहुंचता है। आगामी चुनावों को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि संगठन एकजुट रहेगा तो 2027 में बीजेपी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता।

2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकारें लगातार मजबूत बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल होने जा रहे हैं, जो देश और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है।

चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र

पत्रकारों से बातचीत के दौरान पंचायत चुनाव में देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र है

और बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है।

राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का दावा गलत

सपा सुप्रिमो अखिलेश यादव द्वारा दावा किया गया कि राम मंदिर में चढ़ावे की सत करोड़ रुपये की चोरी हुई है, इन आरोपों पर उन्होंने कहा कि मंदिर से किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई है और इस संबंध में मंदिर ट्रस्ट एवं प्रशासन ही अधिकृत रूप से जानकारी देगा। वहीं नीट पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार ने तत्काल सजा न लेते हुए जांच समिति गठित कर दी है तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। इसी क्रम में जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह एवं पुलिस अधीक्षक चारु निगम ने जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, परीक्षा कक्षों की व्यवस्थाएं, विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया। साथ ही केन्द्र व्यवस्थापकों एवं संबंधित अधिकारियों को परीक्षा की गोपनीयता



एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक चारु निगम ने परीक्षा द्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ द्यूटी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं नकलविहीन वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त

पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन कराने तथा अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। जनपद प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

माता भगवती देवी जी के जन्मशताब्दी वर्ष पर गायत्री परिवार ने लगाया रक्तदान शिविर

सुल्तानपुर। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा रविवार को गोमती ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जहां 60 युवाओं ने गायत्री परिवार की माता भगवती देवी जी को समर्पित करते हुए रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ डॉ. आर.ए. वर्मा, डॉ. सुभाष, पल्लवी वर्मा ने दीप प्रज्वलन एवं पूजन के साथ किया।

डॉ. सुभाष ने कहा कि गायत्री परिवार द्वारा माता भगवती जी को श्रद्धांजलि देने के लिए युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन सराहनीय है। डॉ. आर.ए. वर्मा ने कहा कि रक्तदान महादान है युवाओं को रक्तदान से जुड़कर जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। जिला समन्वयक डॉ. सुधाकर सिंह ने सभी का धन्यवाद दिया। रक्तदान प्रभारी अभिषेक सिंह ने बताया कि गायत्री परिवार द्वारा आगामी रक्तदाता दिवस के दिन भी एक बड़ा शिविर मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में आयोजित किया जाएगा।

आर्यावर्त संवाददाता

बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को उस वक्त बड़ी सफलता मिली, जब कोतवाली शहर पुलिस ने रविवार को एक अहम कार्रवाई करते हुए दो महिला तस्करों को रंगेहा गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिलाओं के कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक और नशे के कारोबार से प्राप्त हुई नकद धनराशि बरामद की गई है।

बिजनौर में स्मैक की पुड़िया बेचने वाली दो सर्गी बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 111.54 ग्राम स्मैक और 88,950 रुपये की नकदी बरामद की गई है। दोनों बहनों का पुलिस ने चालान कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

शनिवार की रात शहर कोतवाल अमर सिंह राठौड़ की अगुवाई में पुलिस ने मोहल्ला मिर्दाना वी निवासी निवासी रहनुमा उर्फ नूरी और तब्बसुम



को दबोच लिया। इनके पास से 50.35 ग्राम स्मैक की डली और 61.19 ग्राम स्मैक छोटी-छोटी पुड़ियों में बरामद हुई। साथ ही स्मैक की पुड़ियों को बेचकर मिली 88,950 रुपये की नकदी भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस की पकड़ में आने वाली दोनों

युवतियां आपस में सगी बहनें हैं। नूरी की उम्र 24 साल है जबकि तब्बसुम, नूरी से छह साल बड़ी है।

पुलिस ने दोनों बहनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इनका चालान कर दिया। शहर कोतवाल अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि

आरोपी बहनों के नेटवर्क और स्मैक की खरीद-फरोख्त से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी तस्दीक किया जा रहा है। साक्ष्य मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली टीम एसआई अंकुरपाल, महिला एसआई ममता आदि शामिल रहे।

भाई पर दर्ज हैं कई केस

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पकड़ी गई दोनों बहनों का भाई नशे का आदी था, जोकि मादक पदार्थ बेचने का काम भी करता था। उसके खिलाफ पहले से ही कई मुकदमें दर्ज हैं। अब वह गंभीर रूप से बीमार है।

इसके बाद दोनों बहनों ने उसके नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए स्मैक बेचने का अवैध धंधा शुरू कर दिया था। तब्बसुम की शादी हो चुकी थी जोकि अब अपनी ससुराल अमरोहा के बजाए अपने मायके बिजनौर में ही रह रही थीं।

कुख्यात भानु प्रताप का अयोध्या में एनकाउंटर, हत्या, लूट, रंगदारी... दर्ज थे कुल 40 मुकदमे

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को रविवार देर रात बड़ी सफलता मिली। 1 लाख 65 हजार रुपये के इनामी और कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह उर्फ बल्लू को अयोध्या में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया। आरोपी पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत गंभीर अपराधों के करीब 40 मुकदमे दर्ज थे। वह लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चर रहा था।

STF को सूचना मिली थी कि भानु प्रताप सिंह अपने एक साथी के साथ बाइक से क्षेत्र से गुजरने वाला है। सूचना के आधार पर टीम ने महाराजगंज थाना क्षेत्र के एमि घाट के पास धेराबंदी कर वाहन चेंकिंग शुरू की। देर रात करीब 11 बजे संदिग्ध बाइक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपियों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।



पुलिस के अनुसार, आत्मरक्षा में STF ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भानु प्रताप सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस

उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

भानु प्रताप सिंह मूल रूप से गोरखपुर जिले का रहने वाला था और पूर्वचल के कई जिलों में उसका आतंक माना जाता था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में

लगभग 40 अपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उसकी गिरफ्तारी पर शासन द्वारा दो लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भानु प्रताप लंबे समय से कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ था। उसकी तलाश में कई जिलों की पुलिस और STF की टीमें लगी हुई थीं।

तालाब पर कब्जे का आरोप, पैमाइश में खानापूर्ति से भड़के ग्रामीण

सुल्तानपुर। बल्दीराय तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत रैचा में तालाबी भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राजस्व विभाग ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई और पैमाइश के नाम पर केवल खानापूर्ति कर दी गई। गांव निवासी अनिल कुमार यादव ने जिलाधिकारी को भेजी शिकायत में कहा है कि तालाब गाटा संख्या 1477 (ख) की भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल जांच केवल एक स्थान पर फीता रखकर औपचारिकता पूरी कर ली। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब की वास्तविक सीमा का निर्धारण किए बिना ही जांच समाप्त कर दी गई।

गरीबों का राशन अटका, एफआईआर वापसी की तैयारी

सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश में गरीब वच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार (टीएचआर) को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि नेफेड और राजस्थान की जेवीएस फूड्स कंपनी के गठजोड़ के चलते प्रदेश के 75 जिलों में पिछले दो महीनों से टेक होम राशन का वितरण प्रभावित रहा, जिससे लाखों लाभार्थियों को पोषण नहीं मिल पाया। अब इस मामले में नया मोड़ तब आया है जब जेवीएस फूड्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं। यही नहीं जिन आरोपों के आधार पर शासन ने खुद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कराई थी, अब उन्हीं आरोपों को कमजोर बनाने की कोशिश हो रही है। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा ने इस मामले की करीब आठ वर्षों तक जांच की। सूत्रों के मुताबिक शुरूआती जांच में गंभीर अनियमितताओं और ठोस साक्ष्यों का दावा किया गया था।

ग्रेट निकोबार बचाओ अभियान अंतर्गत कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में सोमवार को विकास भवन गेट के सामने स्थित राजीव गांधी तिकोनिया पार्क के बाहर ग्रेट निकोबार बचाओ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा आम नागरिकों ने भाग लेकर अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने केंद्र अभियान पर तीखा हमला चलाते हुए कहा कि ग्रेट निकोबार द्वीप केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए पर्यावरणीय नियमों को दरकिनार कर रही है और देश की

अमूल्य प्राकृतिक धरोहर को विनाश के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। राणा ने कहा कि हजारों हेक्टेयर जंगलों की कटाई, दुर्लभ वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों का विनाश और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की अनदेखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि वास्तविक विकास वहीं है जो पर्यावरण संरक्षण और जनहित के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि आज ग्रेट निकोबार संकट में है, कल देश के अन्य वन क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधन भी इसी तरह के खतरों का सामना करेंगे। यह लड़ाई केवल एक द्वीप को बचाने की नहीं, बल्कि देश के पर्यावरण, जलवायु, जंगल, जमीन और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर प्राकृतिक

संसाधनों की लूट और पर्यावरण के विनाश को स्वीकार नहीं करेगी। यदि सरकार ने अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया तो कांग्रेस जनता के साथ मिलकर सड़क से लेकर सदन तक व्यापक जनजाति चलाए के वाध्य होगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ग्रेट निकोबार केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि देश की प्राकृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली योजनाओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना समय की मांग है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने हस्ताक्षर कर ग्रेट निकोबार के संरक्षण के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। कांग्रेसियों ने अधिक से अधिक लोगों से इस अभियान से जुड़ने और पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की है।

मीरजापुर में एआई, सीसीटीवी कैमरे और मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुई पुलसि भर्ती परीक्षा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

मीरजापुर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आरक्षी नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा सोमवार से मजिस्ट्रेट के साथ ही सीसी टीवी कैमरे की निगरानी में 20 केंद्रों पर आरंभ हुई। कड़ी जांच के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया।



रमईपट्टी, आदर्श इंटरमीडिएट कालेज विसुंदरपुर, आर्य कन्या पाठशाला इंटर कालेज गिरधर का चौराहा बासलौगंज, बीएलजे इंटर कालेज, मुकैरी बाजार, बापू उपरीश इंटर कालेज लालगंज, बसंत विद्यालय इंटर कालेज नाराघाट होगी।

जिला विद्यालय निरीक्षक राज कुमार दीक्षित ने बताया कि जीडी बिनानी कालेज भरूहना, गांधी विद्यालय इंटर कालेज कछवां, स्व. काशीराम राजकीय बालिका इंटर

कालेज, महाशक्ति ब्रह्माश्रम इंटर कालेज बिहसड़ा, महेश भट्टाचार्य इंटर कालेज अकोढ़ी, मिश्री लाल इंटर कालेज, राजस्थान इंटर कालेज, राजकीय बालिका इंटर कालेज कछवां बाजार, राजकीय बालिका इंटर कालेज विंध्याचल, श्री माता प्रसाद माता भीख इंटर कालेज, श्री शिव इंटर कालेज, सुंदर मुंदर जायसवाल नगरपालिका बालिका इंटर कालेज बाजीराव कटरा, स्वामी गोविंदाश्रम इंटर कालेज को केंद्र बनाया गया है।

घायल महिला वकील की मौत से साथियों में गम व आक्रोश, प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। पिछले दिनों सड़क हादसे में खम्भी जिस महिला अधिवक्ता के इलाज को लेकर स्वरूपरानी नेहरू (SRN) अस्पताल के जूनियर डॉक्टर और वकीलों के बीच बखेड़ा हुआ था, उस वकील जागृति शुक्ला की मौत रविवार देर रात लखनऊ के एसपीजीआई अस्पताल में हो गई। इसका पता चलते ही प्रयागराज में अधिवक्ताओं के बीच गम और गुस्सा छा गया।

स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में जूनियर डॉक्टरों ने आज सोमवार को हड़ताल कर दी है। सुपर स्पेशलिटी की सभी ओपीडी एक घंटे पहले बंद कर दी गई है। सभी सीनियर डॉक्टर भी चले चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल के चलते तमाम मरीज जो शहर और दूरदराज से आए थे बिना इलाज के ही निराश



होकर लौट रहे हैं। डॉक्टरों में आक्रोश इसलिए हुआ है क्योंकि उनके एक साथी मोहसिन सिद्दीकी को कुछ लोगों ने उठा लिया है जो सादी वदी में थे। बताया जा रहा है कि वकीलों से

मारपीट में यह डॉक्टर आरोपित थे। इससे डॉक्टरों का विरोध और भी बढ़ रहा है। जूंसी निवासी अधिवक्ता जागृति शुक्ला 20 मई 2026 की सुबह हाई

कोर्ट की तरफ जा रही थीं। पोलो ग्राउंड के पास पहुंचते ही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। आनन-फानन में साथी वकील घायल जागृति को इलाज के लिए स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों से विवाद हो गया। उनके बीच मारपीट और जमकर बखेड़ा हुआ था।

अस्पताल में डॉक्टर और सड़क पर अधिवक्ता प्रदर्शन करते रहे, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी। तीसरे दिन वकीलों ने धरना-प्रदर्शन समाप्त किया था। अधिवक्ताओं से मारपीट पर कोतवाली थाने में और टक्कर मारने वाली कार चालक के विरुद्ध सिविल लाइंस थाने में केस लिखा गया था। सिविल लाइंस पुलिस ने कार को सीज कर दिया है। वह आकलैंड कैट निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति की है।

सीएम का जनता दर्शन: मां के साथ पहुंची बेटी, कहा- 12वीं में अच्छे अंक हैं, बीटेक करना चाहती हूं



आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह 'जनता दर्शन' किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए लोगों से उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया। एक बच्ची

ने मुख्यमंत्री से उच्च शिक्षा के लिए मदद की गुहार लगाई, जिस पर उन्होंने कहा कि किसी संस्थान में प्रवेश दिलाने का आदेश दिया। पुलिस की अनसुनी व अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर सख्त सीएम योगी ने अफसरों को मॉनीटरिंग कर पीड़ितों को

न्याय दिलाने का आदेश दिया।

बूढ़ी मां संग आई बेटी, खुश होकर लौटी

लखनऊ की एक बच्ची अपनी बूढ़ी मां के साथ पहुंची। उसने बताया कि इंटरमीडिएट अच्छे अंक से उत्तीर्ण

किया है। वह आगे बीटेक करना चाहती है, लेकिन धन के अभाव में दिक्कत हो रही है। सीएम योगी ने उसकी मार्केट देखी, फिर कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो। आपका प्रवेश किसी अच्छे संस्थान में कराया जाएगा। सरकार किसी भी निर्धन या जरूरतमंद की शिक्षा को वापिस नहीं होने देगी। सकारात्मक संदेश पाकर प्रफुल्लित बेटी व मां ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।

मॉनीटरिंग कर पीड़ितों को न्याय दिलाइए

विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों ने मुख्यमंत्री से पुलिस की हीलाहवाली व अवैध कब्जे को लेकर उचित कार्रवाई न होने की शिकायत करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने हर प्रकरण को सुना, फिर शासन के अफसरों को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि इन मामलों की मॉनीटरिंग करिए।

पीड़ित को न्याय और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराइए। सीएम ने पीड़ितों को जल्द ही समाधान के लिए आश्वासन दिया।

पहले जनपद, मंडल के अधिकारियों से अवश्य मिलिए

कुछ फरियादी ऐसे भी आए, जो सीधे 'जनता दर्शन' में पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि आपने जनपद के किस अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी। इस पर कुछ फरियादियों ने कहा कि हम सीधे यहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गर्मी वेतहासा पड़ रही है। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सबसे पहले अपनी शिकायतें जनपद, मंडल स्तर के अधिकारियों से करें। कई समस्याओं का समाधान वहीं से हो जाएगा।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन में सुनीं सैकड़ों समस्याएं

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने कैम्प कार्यालय, 7 कालिदास मार्ग, लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए सैकड़ों नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित, प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे, जिनके लिए शीतल पेयजल, शरबत एवं मिठाई की विशेष व्यवस्था की गई थी। उप मुख्यमंत्री स्वयं लोगों के बीच पहुंचे और एक-एक फरियादी की समस्या को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना। कार्यक्रम में भूमि एवं राजस्व विवाद, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, विद्युत एवं पेयजल, पुलिस प्रशासन, शिक्षा तथा रोजगार से जुड़े अनेक प्रकरण प्रस्तुत किए गए। उप मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मामले का संज्ञान

लेते हुए अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन केवल शिकायत सुनने का मंच नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास एवं संवाद का सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से शासन-प्रशासन को जमीनी वास्तविकताओं की जानकारी मिलती है और समस्याओं के समाधान में तेजी आती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को न्याय दिलाने और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और पीड़ित को न्याय पाने के लिए सहायता नहीं पड़ेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का सम्यक् और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही शिकायतों के समाधान में

जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया। विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंदों की समस्याओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की संवेदनशीलता का वास्तविक स्वरूप तभी दिखाई देता है जब कमजोर वर्गों को समय पर राहत और न्याय मिलता है। भूमि विवाद और अवैध कब्जों से जुड़े मामलों पर उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों से मौके पर जांच करवाकर निष्पक्ष और तथ्यांवी समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। जनता दर्शन के दौरान उप मुख्यमंत्री ने फरियादियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का हर संभव समाधान कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल शिकायतों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि परदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन स्थापित करना है।

दुष्कर्म के आरोपी सगे मामा को 24 घंटे में गिरफ्तार, भेजा गया न्यायालय

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। थाना बन्धरा पुलिस ने दुष्कर्म के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सगे मामा को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर नरायनपुर तिराहा क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। मामले में पीड़िता की माता की तहरीर पर तत्काल अभियोग दर्ज कर कठोर धाराओं में विधिक कार्रवाई शुरू की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता की माता द्वारा दी गई लिखित तहरीर में बताया गया कि उनकी पुत्री कुछ दिन पूर्व अपनी ननिहाल जनपद लखनऊ गई थी। आरोप है कि इसी दौरान अभियुक्त ओमकार पुत्र राधेश्याम, जो निवासी जनपद लखनऊ, ने पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर उसे घायल किया और इसके बाद अपनी भांजी के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध कारित किया। तहरीर के

आधार पर थाना बन्धरा में मु0अ0सं0-167/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2)/65(1) एवं पॉसो एक्ट की धारा 3/4(2) में मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम का गठन कर आरोपी को गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशा दी गई। पुलिस टीम ने साक्ष्य संकलन और मुखबिर तंत्र के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को 08 जून 2026 को नरायनपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की उम्र लगभग 32 वर्ष बताई गई है। गिरफ्तारी के बाद उसे नियमानुसार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस पृष्ठताछ के दौरान आरोपी ने प्रारंभिक रूप से घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए कहा कि उससे गलती हो गई है।

• संक्षेप •

दुबग्गा क्षेत्र के दबंग व्यक्ति पर बड़ी कार्रवाई, 06 माह के लिए जिला बंदर का आदेश जारी

लखनऊ। पुलिस कमिश्नर लखनऊ में लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से थाना दुबग्गा क्षेत्र के एक मनबद एवं दबंग व्यक्ति के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यायालय पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा आरोपी को 06 माह के लिए लखनऊ की सीमा से निकालित (जिला बंदर) करने का आदेश पारित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई संरक्षित वाद संख्या 41(09)/2026 के अंतर्गत की गई, जिसकी सुनवाई न्यायालय पुलिस आयुक्त लखनऊ में हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया, जिसके बाद राज्य की ओर से उपस्थित संयुक्त निदेशक अभियोग्य श्री अवैध कुमार सिंह ने कड़े तर्क प्रस्तुत करते हुए आरोपी के विरुद्ध जिला बंदर की कार्रवाई को उचित बताया। अभियोग्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रमाणों में उपलब्ध अभिलेखों के गहन परीक्षण के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संबंधित व्यक्ति की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक है। इसके आधार पर उसे गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ जनपद की सीमा से 06 माह के लिए निकालित करने का आदेश दिया गया। आदेश के अनुसार, जिला बंदर किए गए व्यक्ति की पहचान आसिफ उर्फ शाहरुख (उम्र 22 वर्ष), पुत्र नबा, निवासी गद्दी बगिया, ग्राम सिकरी, हरदोई रोड, थाना दुबग्गा, लखनऊ के रूप में हुई है। अभिलेखों के अनुसार आरोपी के विरुद्ध कई गंभीर अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, हत्या के प्रयास, चोरी, पशु क्रूरता, गोधन निगारण अधिनियम, एससी/एसटी एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामले शामिल हैं। पुलिस प्रशासन के अनुसार आरोपी की अपराधिक गतिविधियों को देखते हुए यह कदम जनहित एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक था। इस आदेश के बाद आरोपी को आगामी 06 माह तक लखनऊ जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस कमिश्नर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इसी प्रकार कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

पादप स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर बीबीएयू में हुआ विशेष व्याख्यान, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रभावी नीतियों पर दिया गया जोर

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में रविवार को एमिनेंट लेक्चर समिति, आंतरिक गुणवत्ता आवासन प्रकोष्ठ तथा सतत विकास लक्ष्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में एमिनेंट लेक्चर सीरीज के अंतर्गत 'पादप स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा' विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय प्लॉट पैथोलॉजिस्ट एवं सिरमट एनालिस्ट तथा फूड सिक्योरिटी जर्नल के एडिटर-इन-चीफ Serge Savary मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति S. Victor Babu ने की। इस अवसर पर एमिनेंट लेक्चर सीरीज समिति की अध्यक्ष प्रो. शिल्पी वर्मा तथा सतत विकास लक्ष्य समिति के अध्यक्ष प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा भी मंचासीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं बाबासाहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके बाद विश्वविद्यालय कुलगीत का गायन हुआ। अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं पीषा भेंट कर स्वागत किया गया। अपने स्वागत संबोधन में प्रो. शिल्पी वर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी दी, जबकि प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा ने मुख्य अतिथि का परिचय प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रीति गुप्ता ने किया। मुख्य अतिथि प्रो. सर्ज सावेरी ने अपने व्याख्यान में पादप रोगों, कीटों और अन्य कारकों से होने वाली क्षति तथा कृषि उत्पादन पर उनके प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पीषा की बीमारियों और फसल क्षति के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जेनेरिक मॉडर्निज फ्रेमवर्क, क्षति आकलन प्रणाली तथा महामारी विज्ञान की अवधारणाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

47 यात्रियों की क्षमता वाली बस में मिले 167 यात्री, इमरजेंसी गेट पर लगी थी बेंचे, लखनऊ में की गई सीज

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में जांच के दौरान बिहार से पंजाब जा रही स्लीपर बस में 167 यात्री मिले। जबकि, बस की क्षमता 47 यात्रियों की थी। परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने बस को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सीज कर दिया। यात्रियों को छतों पर भी बिठाया गया था।

मामला स्लीपर बस संख्या यूपी 11 बीटी 0077 का है। यह बस बिहार के मुजफ्फरपुर से पंजाब के पटियाला के लिए जा रही थी। एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डगमेगार बसों की जांच कर रहे थे। इसी बीच तल्ले के पास स्लीपर बस आती हुई दिखाई दी, जिसकी छत पर ढेरों यात्री बैठे हुए थे। प्रवर्तन टीम ने बस को रुकवाया और जांच की। इसमें 167 यात्री पाए गए। कांचों की पड़ताल में बस का आल ईंडिया परमिट भी समाप्त पाया गया। बस में



यात्रियों की स्वीकृत क्षमता 47 यात्रियों की थी। यात्रियों को उतारकर बस सीज कर दी गई।

खड़ी थी इंटरसेप्टर, नहीं दिखी स्लीपर बस

सूत्रों ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जहां कार्रवाई हुई है, वहीं पर परिवहन विभाग के दो इंटरसेप्टर भी खड़े थे। लेकिन इस पर तैनात अफसरों को स्लीपर बस नजर नहीं आई। ऐसे में अफसरों की कार्यप्रणाली

सवाल के घेरे में है।

इमरजेंसी गेट की जगह लगी थी बेंचे, छत पर भी बैठे थे यात्री

स्लीपर बस की बनावट से भी छेड़छाड़ की गई थी। बस में अंदर इमरजेंसी गेट के पास बेंचे लगाई हैं थीं। पैसेज ने भी यात्रियों को बिठाया गया था। इतना ही नहीं यात्रियों को बस की छत पर भी बिठाकर यात्रा कराई जा रही थी।

माल क्षेत्र में पत्नी की हत्या, आरोपी पति हिरासत में— फॉरेंसिक जांच जारी, विधवा संवत की आशंका

लखनऊ। थाना माल क्षेत्र के आजाद नगर में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की चाकू से वार कर हत्या कर दिए जाने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही थाना माल पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आजाद नगर निवासी लगभग 55 वर्षीय जितेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह ने अपनी पत्नी मोनिका सिंह (उम्र लगभग 47 वर्ष) पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतका का शव घर के एक कमरे से बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को सुरक्षित किया और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शुरू कर दी। घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि मामले की हर धेलाख से जांच का सके।

यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू

» भर्ती परीक्षा को लेकर नागरिक सुरक्षा अलर्ट, स्टेशन और बस अड्डों पर सहायता केंद्र संचालित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती-2025 की तीन दिवसीय लिखित परीक्षा आज से शुरू हो गई है। यह परीक्षा 8, 9 और 10 जून को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों के लिए 28,86,797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा हर दिन दो पालियों में आयोजित की जा रही है। पहले दिन

की पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। हर पाली में लगभग 4.81 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं।

परीक्षा को सुचारु रूप से कराने के लिए पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, स्टैटिक मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षक और पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है।

भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की मदद को आगे आई नागरिक सुरक्षा : जिले में आयोजित हो रही भर्ती परीक्षा के मद्देनजर नागरिक सुरक्षा की टीमों ने बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं। इन हेल्प डेस्क के माध्यम से दूर-दराज से आने वाले अभ्यर्थियों को

परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने, परिवहन संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इन टीमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा में शामिल होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को जानकारी के अभाव या अन्य कठिनाइयों के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े।

नागरिक सुरक्षा की यह पहल अभ्यर्थियों के लिए राहत और सहयोग का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की निगरानी उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। सरकार की ओर से परीक्षा के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई है, जिसमें अतिरिक्त बसों का संचालन भी शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए एडमिट कार्ड दिखाने पर बस किराए में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है।

परीक्षा संपन्न, अभ्यर्थियों ने साझा किए अनुभव, 28 लाख अभ्यर्थी हो रहे शामिल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज से शुरू हो गया है। सोमवार से बुधवार तक लिखित परीक्षा योजना दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। उप पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अब तक 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं।

भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी एसबी शिराडकर ने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए पुष्टा बंदोबस्त किए गए हैं। सभी नोंडल अधिकारियों द्वारा परीक्षा केंद्रों तक सही प्रश्न पत्र भेजने की जिम्मेदारी दी गई है। रविवार शाम से ही सभी केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सोमवार को परीक्षा के पहले दिन



कड़ी चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश करने दिया जाएगा। इससे पहले उनके आधार कार्ड का सत्यापन और ई-केवाई की प्रक्रिया भी होगी। अभ्यर्थियों को आइरिस जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं स्थानीय पुलिस और एसटीएफ सँदिधों पर नजर रखने के साथ धरपकड़ करेगी। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वह जूते के बजाय चप्पल पहनकर आएँ। परीक्षा केंद्रों के आसपास के इलाकों में भी सतर्कता बरती जाएगी। बोर्ड के अपर सचिव भर्ती संस्था में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

की प्रत्येक पाली में करीब 4.90 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। बता दें कि सिपाही बनने के लिए करीब 28.65 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सभी जिलों में परीक्षा के लिए 1183 केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। महिला अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए भर्ती बोर्ड ने उनके गृह जनपद के मंडल वाले जिलों में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया है। साथ ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के दौरान चेकिंग के लिए बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर संजय सिंह का भाजपा और ट्रस्ट पर हमला

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले को लेकर भाजपा और राम मंदिर ट्रस्ट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में लगातार देश के संसाधनों, संस्थानों और जनता के अधिकारों पर प्रश्न उठते रहे हैं, और अब भगवान श्रीराम के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित धन में गड़बड़ी के आरोप सामने आना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार यह सवाल उठाया जा रहा है कि राम मंदिर के दान पात्र और चढ़ावे में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि शुरुआत में इन आरोपों को नकारा गया, लेकिन अब सामने आई जानकारी के अनुसार इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं और जांच एजेंसियों

को कार्रवाई करनी पड़ी है, जिससे स्थिति गंभीर प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रामभक्त अपनी आस्था और मेहनत की कमाई भगवान श्रीराम के चरणों में अर्पित करते हैं, ऐसे में उस धन की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि यदि चढ़ावे में अनियमितता के तथ्य सामने आ रहे हैं तो यह सीधे-सीधे श्रद्धालुओं की आस्था पर आघात है और इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा पर पहले भी सरकारी संपत्तियों के निजीकरण के आरोप लगाए रहे हैं, और अब यदि धार्मिक आस्था से जुड़े धन पर भी सवाल उठते हैं तो यह बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि जनता जानना चाहती है कि इस कथित गड़बड़ी के पीछे कौन जिम्मेदार है और यह कैसे संभव हुआ।

लखनऊ के दारोगा भी सेफ नहीं! जालसाजों ने मोबाइल हैक कर पार किए 164000 रुपये



आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। लखनऊ की दारोगा के साथ हुए धोखे की कहानी चर्चा में है। महिला दारोगा का आरोप है कि जालसाजों ने उनके खाते से पैसे उड़ा लिए हैं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, घटनाक्रम के बाद सवाल उठने लगे हैं कि जब पुलिस अधिकारी के साथ ऐसा धोखा से जांच का सके।

जनता के पैसे कैसे सुरक्षित रह सके?

महिला दारोगा द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया कि साइबर ठगों ने उनका मोबाइल हैक कर लिया था। इसके बाद उनके बैंक खाते से 1.64 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित महिला बीकेटी थाना में दारोगा के पद पर तैनात हैं।

4 जून को दोपहर करीब 1:45 बजे महिला दारोगा का फोन अचानक आँटो अपडेट होने लगा। पीड़िता को लगा कि मोबाइल अपडेट हो रहा है,



कर्नाटक : डीके शिवकुमार के सीएम होने के मायने

28 मई को अंततः कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सियासत की दरोदोवार पर अटकलों और कयासों के सब्जे उगने का दौर तब थम गया, जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। इसके लिये उन्होंने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को अपने सरकारी आवास पर सुबह के नाश्ते पर आमंत्रित किया और बीते तीन साल में उनके सहयोग के लिए आभार जताते हुये कहा कि वह अपरान्ह तीन बजे इस्तीफा देने राजभवन जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस विधायकों से जब उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सहयोग की बात कही, तो यह स्पष्ट हो गया कि शिवकुमार उनके उत्तराधिकारी होंगे। मई का महिना शिवकुमार के लिए बड़ा मायने रखता है। उनका जन्म आज से चौंसठ साल पहले 15 मई को कनकपुरा में हुआ था और सन 2023 में मई माह में ही उनके अथक प्रयासों से बीजेपी की यैदियुग्मा- सरकार को अपदस्थ कर कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। यह दौर है कि जीतोड़ कोशिशों के बाद डीकेएस तब सीएम नहीं बन सके थे और उनसे वरिष्ठ और अनुभवी सिद्धारमैया ने बज्रदि बाजी मार ली थी। बहरहाल, 28 मई को डीकेएस को सुबह का ब्रेकफास्ट उनके अपने जन्मदिन और कांग्रेस सरकार की सालगिरह के समारोह के नाशतो से अधिक सुखद और लज्जतदार लगा होगा, क्योंकि इस रोज उनका पालित सपना या सपना पूरी हुई।

डीकेएस यानि डोडालाहल्ली केपैगौड़ा शिवकुमार कर्नाटक के शीर्षस्थ नेताओं में शुमार हैं। वह धनाढ्य हैं, लोकप्रिय हैं, जुझारू और दबंग हैं और कुशल रणनीतिकार हैं। वह महत्वाकांक्षी हैं। करीब चार दशकों का उनका सियासी सफर दिलचस्प और घटनाप्रधान रहा है। वह खांटी कांग्रेसी हैं और सोनिया गांधी के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है। तीन साल पहले कर्नाटक में सत्ता में कांग्रेस की वापसी पर उन्होंने सोनियाजी से अपना कौल निभाने की बात कही थी। डीकेएस का कॉन्फिडेंस लेबेल गजब का है। उन्हें जायंट-किलर यूँ ही नहीं माना जाता। पहलेपहल उन्हें इस विशेषण से तब नवाजा गया था, जब सन 1989 में सथानूर से एचडी देवेगौड़ा को हराया था। इसी क्रम में उन्होंने एचडी कुमारस्वामी, पीजीआर सिंधिया और अनिता कुमार स्वामी को भारी मतों के अंतर से परास्त किया। देवेगौड़ा परिवार की त्रयी को हराने की तिकड़ी उनके खाते में दर्ज है। सन 2018 में उनकी जीत का अंतर अस्सी हजार से अधिक मतों का था। सन 2019 की भगवा लहर में भी वह अपने भाई डीके सुरेश को लोकसभा के लिए जिताने में कामयाब रहे। उनकी ब्यूह रचना का लोहा उनके विरोधी भी मानते हैं। वह कुबेर राजनेता हैं और सन 2018 में चुनावी हलफनामे में उन्होंने 840 करोड़ की संपत्ति दर्शाई थी। डीकेएस का जीवन संघर्षों से बिंधा रहा है। सन 2017 में उनके दफ्तरो, ठिकानों और बिड़ड़ी में इंगलटन गोल्फ रिजॉर्ट पर आयकर छापा पड़ा। उनके बंगलौर, चेन्नै, दिल्ली और मैसूरू के 67 ठिकानों पर तीन सौ अफसरों ने अस्सी घंटे छानबीन की। मौके पर सीआरपीएफ की तैनाती हुई। करीब दस करोड़ की संपत्ति जप्त हुई। अग्रिम जमानत के बावजूद तीन सितंबर, 2019 को उन्हें गिरफ्तार किया गया और डेढ़ माह से अधिक का समय उन्हें तिहाड़ जेल में बिताना पड़ा। उन पर मनी लॉडिंग, कर वंचन, अवैध खनन के आरोप लगे, लेकिन वह डिगे नहीं और सोनिया-राहुल के प्रति अडिग वफादारी के सुबुत देते रहे।

दिल्ली में गत दिनों मैराथन बैठकों ने संकेत दिया था कि कर्नाटक की देगची में नेतृत्व परिवर्तन की खिचड़ी पक रही है। सिद्धारमैया ने कहा भी कि वह केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर त्यागपत्र दे रहे हैं। कर्नाटक-प्रभारी सुरजेवाला इसे पॉवर-शेयरिंग नहीं मानते, लेकिन यह तय है कि डीकेएस के सन्न का प्याला छलकने की वेला आ सकती थी। कर्नाटक में 224 के सदन में कांग्रेस के 136, बीजेपी 63 और जेडीएस के 18 विधायक हैं। इसके बावजूद कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष विजयेंद्र के कथन कि कर्नाटक में समय पूर्व चुनाव को कोई रोक नहीं सकता, ने धुकधुकी बढ़ा दी है। सीएम के विधि सलाहकार पोन्नना भी वेट एंड वाच की बात कह रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत राजधानी के बाहर हैं और मुख्यमंत्री से उनके रिश्ते जगजाहिर हैं। कोई नहीं जानता कि सिद्धारमैया की भूमिका क्या होगी, मगर कांग्रेस के लिए कर्नाटक बड़ा मायने रखता है और तीन साल बाद ही सही डीकेएस के लंबों और प्यालों के बीच फासला मिटता दिख रहा है। नेतृत्व परिवर्तन के प्रसंग का पटाक्षेप इस तरह हुआ कि शिवकुमार ने सिद्ध के पांव छुवे और सिद्ध ने उन्हें गले लगाया।

आखिर कैसे रूकेंगे मालवीय नगर होटल अग्निकांड जैसे हादसे, जिम्मेदार कौन?

कमलेश पांडे

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल-अग्निकांड में 21 लोगों की मृत्यु और दर्जनों के घायल होने की घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सुरक्षा नियमों की संभावित विफलता और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली या अन्य महानगरों में हुई ऐसी ही घटनाओं से सिविल/पुलिस प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली, जिससे यह हादसा भी नियति का खेल बनकर रह गया। प्रशासन को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे, जिससे इतनी भारी क्षति नहीं हो पाए।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, भवन में केवल एक प्रवेश-निकास मार्ग था, बेसमेंट और उपरी मंजिलों में क्षमता से अधिक कमरे संचालित किए जा रहे थे, तथा अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन पर भी सवाल उठ रहे हैं। लिहाजा यह प्रश्न मौजू है कि आखिर इस लोमहर्षक और दर्दनाक घटना का जिम्मेदार कौन? यह ठीक है कि जांच पूरी होने से पहले अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन सामान्यतः ऐसी घटनाओं में जिम्मेदारी कई स्तरों पर तय होती है जो इस प्रकार से समझी जा सकती है:-

पहला, होटल मालिक और अदृग्दर्शी प्रबंधन-यदि बिना वैध अग्नि सुरक्षा अनुमति (Fire NOC) के संचालन हुआ। यदि निर्धारित क्षमता से अधिक कमरे या अवैध निर्माण किए गए। यदि आपातकालीन निकास, अलार्म और अग्निशमन उपकरण पर्याप्त नहीं थे। तो इसका सीधा तातपर्य है कि होटल मालिक के अदृग्दर्शी प्रबंधन ने लोगों को अप्रत्याशित मुसीबत की आग में झुलसने को मजबूर कर दिया और समय पर समुचित मदद उन्तक नहीं पहुंच पाई। यह जांच का विषय है और शायद इसी वजह से होटल मालिक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया है।

दूसरा, लाइसेंस और निरीक्षण देने वाली एजेंसियां: यदि नियमों के उल्लंघन के बावजूद संचालन जारी रहा। यदि नियमित निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित रहे, तो लाइसेंस जारी करने और निरीक्षण देने वाली एजेंसियों पर उंगली उठनी स्वाभाविक बात है, क्योंकि इनकी लापरवाही या मिलीभगत से न केवल जान-माल की भारी क्षति



हुई, बल्कि केंद्र व राज्य सरकार के गुणवत्ता हीन विकास और कथित सुरासन के दावों की भी हवा निकल गई। चूंकि इस अग्निकांड के विदेशी नागरिक भी शिकार बताए जाते हैं, इसलिए विदेशों में भारत की बदनामी स्वाभाविक है और इससे दिल्ली समेत देश का पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो सकता है।

तीसरा, स्थानीय प्रशासन और नगर निकाय: अवैध निर्माण, क्षमता से अधिक उपयोग और सुरक्षा उल्लंघनों की समय रहते पहचान न कर पाना भी जांच का विषय है। चूंकि स्थानीय प्रशासन और नगर निकाय से जुड़े जिम्मेदार लोग भी यदि समय रहते ही खामियां पकड़ लिए होते और स्पष्ट कार्रवाई किये होते तो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की इतनी बदनामी नहीं होती।

इसलिए यक्ष प्रश्न समुपस्थित है कि आखिर कबतक ऐसे दर्दनाक हादसे रूकेंगे और कैसे रूकेंगे? इसका जवाब निम्नतम हो सकता है:-

पहला, शून्य-सहनशीलता नीति: बिना Fire NOC वाले होटल, गेस्ट हाउस और रेस्तरां तत्काल बंद किए जाएं। दूसरा, डिजिटल और सार्वजनिक निरीक्षण: सभी होटलों की अग्नि सुरक्षा स्थिति ऑनलाइन सार्वजनिक हो ताकि ग्राहक भी देख सकें कि होटल सुरक्षित है या नहीं। तीसरा, बहु-निकास अनिवार्य: एक ही प्रवेश-निकास वाले

भवनों को होटल या व्यावसायिक उपयोग की अनुमति न दी जाए। चौथा, आपातकालीन अभ्यास: होटल कर्मचारियों और अतिथियों के लिए नियमित फायर ड्रिल अनिवार्य हो। पांचवां, व्यक्तिगत जवाबदेही: केवल जुमाना नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही साबित होने पर होटल मालिकों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो। छठा, नागरिक जागरूकता: होटल में ठहरते समय लोगों को भी आपातकालीन निकास, अग्निशमन यंत्र और सुरक्षा संकेतों पर ध्यान देना चाहिए।

इस घटना से हमें व्यापक सबक मिलती है, क्योंकि यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि भारत में कई बार हादसों के बाद जांच और मुआवजे की घोषणा तो होती है, लेकिन सुरक्षा संस्कृति में अपेक्षित बदलाव नहीं आता। 2019 के दिल्ली होटल अग्निकांड सहित कई बड़ी आग की घटनाओं के बाद भी वही समस्याएं—एकमात्र निकास, अवैध निर्माण, और सुरक्षा मानकों की अनदेखी—दोहराई जाती रही हैं। ऐसे में फिर यदि जांच में सुरक्षा नियमों की अनदेखी सिद्ध होती है, तो जिम्मेदारी केवल होटल मालिक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उन सभी संस्थाओं और अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए जिनकी निगरानी में यह व्यवस्था चल रही थी।

टिप्पणी

स्कूली शिक्षा गंभीर संकट का सामना कर रही



शिक्षा का प्रसार करने में भारत सफल है, मगर स्कूल से यूनिवर्सिटी तक लर्निंग क्वालिटी, तर्क-बुद्धि, शिक्षक क्षमता और रोजगार लायक योग्यता प्रदान करने के मामले में वह गहरे संकट का सामना कर रहा है।

गुणवत्ता संपन्न ज्ञान एवं तर्क क्षमता प्रदान करने के मामले में भारत की स्कूली शिक्षा गंभीर संकट का सामना कर रही है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट- "भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली: सामयिक विश्लेषण एवं गुणवत्ता वृद्धि के लिए नीतिगत मार्ग - में यह बात स्वीकार की है। आयोग ने ये विस्तृत रिपोर्ट यूडीआईएसई+, एनएएस, प्रदर्शन आकलन समीक्षा, परख और असर रिपोर्टों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार की है। एक वाक्य में इसका सार है- शिक्षा का प्रसार करने में भारत ने सफलता हासिल की है, मगर लर्निंग क्वालिटी, शिक्षक क्षमता, और रोजगार पाने लायक योग्यता प्रदान करने जैसे मामलों में वह गहरे संकट का सामना कर रहा है।

प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक यही सूरत मौजूद है। स्पष्टतः शिक्षा के प्रसार से मतलब स्कूलों में दाखिले से है। आज देश में 14.7 लाख स्कूल, त्करीबन 24.7 करोड़ बच्चे और एक करोड़ शिक्षक हैं। मगर बुनियादी ज्ञान प्राप्त एवं प्रदान करने के मोर्चे पर स्थिति नाजुक है। ऊंचे क्लास में पहुंच जाने के बावजूद ज्यादातर छात्र निचले वर्ग का पाठ पढ़ने या अंकगणित के प्रश्नों को हल करने में नाकाम बने रहते हैं। क्लास बड़ने के साथ समस्या बढ़ती चली जाती है। कई राज्यों के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता कमजोर है, शिक्षा का स्तर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं है, शिक्षा संस्थान फंडिंग और संचालन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हैं और इन सबका नतीजा है कि डिग्री लेकर निकले छात्रों को बाजार रोजगार के योग्य नहीं मानता।

आयोग ने कहा है कि बिखराव- ग्रस्त स्कूल प्रणाली, शिक्षकों की कमी, और असमान लर्निंग की स्थिति जैसे मसलों को हल नहीं किया गया, तो प्रगति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकेगा। रिपोर्ट में शिक्षा व्यवस्था में आमूल सुधार की जरूरत बताई गई है। आधुनिक दौर के मूलाधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित करने का सुझाव दिया गया है। मगर ये होगा कैसे? बजट पर गौर करें, तो साफ है शिक्षा सरकारों की प्राथमिकता नहीं है। उपर से ज्ञान एवं तर्क विक्रोही माहौल राजनीतिक परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। ऐसे में छात्र सीखने एवं तर्क करने की दिशा में कैसे प्रेरित होंगे?

ब्लॉग

देश की सुरक्षा एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

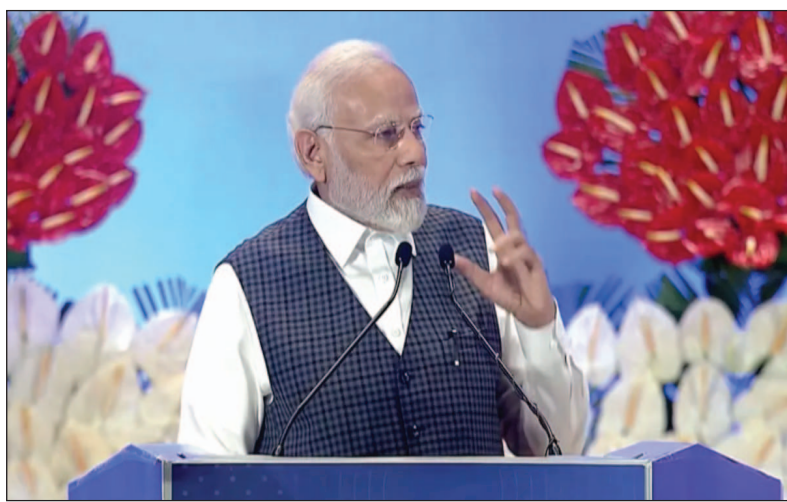


शिवप्रकाश

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 जून को संवैधानिक चुनाव पद्धति से चयनित सबसे अधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हो जायेंगे। मोदी देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का 4398 दिनों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर 4399 दिन अपनी देश सेवा के पूर्ण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री दोनों के कार्यकाल को जोड़कर 25 वर्षों के साथ ही 9007 दिनों की अनवरत राष्ट्र सेवा को भी पूर्ण करेंगे। यह उत्साही, अविश्रान्त, अनथक कर्मयोगी की यात्रा है।

देश के विकास के लिए अनेक कीर्तिमान गढ़ने वाले कठोर निर्णयों के लिए तो 12 वर्षों का उनका कार्यकाल अविस्मरणीय रहेगा ही साथ-साथ देश की सुरक्षा के लिए भी उनके योगदान और भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए उन्होंने आतंकवाद से प्रति जीरो टॉलरेंस (ZERO TOLERANCE) की नीति को अपनाया। 13 जून 2014 को भारतीय सेना के साउथ ब्लॉक में स्थित रक्षा वॉर रूम में सेना उच्च अधिकारियों के साथ संवाद एवं रक्षा तैयारियों की समीक्षा कर ही अपनी सुरक्षा के प्रति प्राथमिकता को स्पष्ट कर दिया था। जब समस्त देश दीपावली पर दीपों से अपने-अपने घरों को प्रकाशमान करता है तब प्रधानमंत्री सीमा पर सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच में उपस्थित रहकर देश उनके साथ है ऐसा संदेश देते हैं। सियाचिन से प्रारंभ कर 12 वर्षों में 12 स्थानों पर जाकर उन्होंने अपनी सीमा सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की है।

आचार्य चाणक्य ने राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भ में कहा था कि "मजबूत सेना के बिना राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता। 1962 में चाइना युद्ध में हमारी पराजय तथा 1964 में चाइना के परमाणु परीक्षण के बाद निर्मित निराशाजनक स्थिति से उबारने के लिए भारत को भी परमाणु शक्ति युक्त होना चाहिए, यह मांग जनसंघ ने 4 दिसम्बर 1964 को पटना अविवेशन में की थी। तब कांग्रेस सहित समस्त दलों ने इस मांग का उपहास किया था। जनसंघ के इसी संकल्प की पूर्ति को 11 मई 1998 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण विस्फोट कर पूर्ण किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद



2014 रक्षा विभाग का बजट 2.27 लाख की तुलना में 3 गुना 7.85 लाख करोड़ हो गया। आज हम 100 से अधिक देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेच रहे हैं। अब हमारा निर्यात में 2014 की तुलना में 686 करोड़ से बढ़कर 2025 -26 में 38424 करोड़ अर्थात् 56 गुना वृद्धि हुई है। अब हम हाइपर सोनिक मिसाइल, ब्रह्मोस, बैलिस्टिक मिसाइल, एयर डिफेंस एवं रडार सिस्टम को ध्वस्त करने वाले रुद्रम -2, प्रलय, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल बना रहे हैं। भारत का स्वदेशी आईएनएस विक्रान्त, रफेल, एस - 400 विमानों से हम युक्त हैं। आर्मीनया ने येरेवान रिपब्लिक स्क्वायर में भारत में बनी "आकाश" एयर डिफेंस मिसाइल एवं पिनका रॉकेट लौनचर्स का प्रदर्शन भारतीयों को मस्तक ऊंचा करता है। 15 अगस्त 2025 को लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "स्वदेशी क्षमताओं, मेड इन इंडिया हथियारों ने सिद्ध किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा विदेशी निर्भरता पर नहीं टिक सकती।" इसी का परिणाम ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने 22 मिनट में ही सभी निर्धारित लक्ष्य पूर्ण कर किए थे। 72000 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली ग्रेट निकोबार परियोजना भारत की आर्थिक समृद्धि, सामुद्रिक रणनीति एवं सुरक्षा का आधार बनेगी।

सेना में स्वदेशी रक्षा उत्पाद, रक्षा बजट में वृद्धि, सेना के आधुनिकीकरण के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा पर सफलता प्राप्त करना ऐतिहासिक कदम है। 2014 से पूर्व पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद चरम पर था। केवल कश्मीर ही नहीं देश का कोई शहर सुरक्षित नहीं था। मुंबई, जयपुर, दिल्ली, काशी सहित अनेक आतंकी घटनाएं आज भी हमको विचलित करती हैं। सुरक्षाबलों को आधुनिक शस्त्र, बुलेट प्रूफ जैकेट, टैरर फंडिंग पर रोक हेतु "NO MONEY FOR TERROR" जैसे कड़े कदम, FATA के माध्यम से वित्तीय दबाव के साथ सर्जिकल एवं बालाकोट एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने का कार्य किया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में स्थापित आतंकी

केंद्रों का सफाया एवं पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र को ध्वस्त किया। 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय कर देश की एकात्मता को सुदृढ़ किया है।

इस ऐतिहासिक दिन को देश ही नहीं सम्पूर्ण विश्व स्मरण करेगा जब हमने कहा कि 31 मार्च 2026 वामपंथ प्रेरित नक्सलवाद से हम मुक्त हो रहे हैं। 2024 में 126 जिले नक्सलवादी आतंक से युक्त थे। 2024 में ही केवल 290 नक्सली मारे गए। 1090 गिरफ्तार हुए। 881 ने आत्मसर्पण कर भारत की मुख्यधारा में लौटने का संकल्प किया। अब बस्तर सहित सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की ब्यार बह रही है।

युसुफैटिये देश की लोकातांत्रिक व्यवस्था, सुरक्षा के लिए खतरा एवं जनसांख्यिकी असंतुलन निर्माण कर रहे हैं। भारत सरकार ने इस संकट से उबरने के लिए "डिटेक्ट", डिलीट, डिपोस्ट" नीति के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की है। सीमा की निगरानी को सख्त किया है। बंगाल भाजपा विजय के पश्चात् बांग्लादेशी घुसपैठियों की बांग्लादेश की ओर वापसी की लाइन हम देख रहे हैं। 15,106 किलोमीटर सीमा "सोती रेखा से जागती दीवार" लक्ष्य में Laser Wall, Vibration sensors, Night vision camera का उपयोग हो रहा है। सीमा सुरक्षा के लिए 49 % बजट वृद्धि कर 5597 करोड़ निर्धारित किया गया है।

अदृश्य युद्ध के माध्यम से भारत को साइबर सुरक्षा को चुनौती देने का कार्य भारत विरोधी शक्तियां कर रही हैं। राज्यसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत ने लगभग 54 लाख साइबर शिकायतों एवं 31594 करोड़ रूपयों के ठगी के प्रयासों का सामना करने में भारत सफल रहा। भारत सरकार ने 2024 में साइबर कमांडो व्यवस्था निर्माण का साइबर सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की है। DCYA (DEFENCE CYBER AGENCY) एवं I4C के माध्यम से समन्वय कर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रयास हो रहा है। देश को नशामुक्त बनाने हेतु व आतंकवाद जैसी

समस्याओं के आय के प्रमुख स्रोत ड्रग्स के गैर कानूनी व्यापार पर करारा प्रहार करते हुए लगातार उनको जन्त किया जा रहा है। 2024 में ही 25,330 करोड़ रुपये के ड्रग्स की जन्ती इस बात का पुख्ता प्रमाण है।

सीमा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान सीमावर्ती गाँव में बसे ग्रामीणों का रहता है। उनके मन में अपने प्रति उपेक्षा भाव न रहे इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 में कहा, "ये अंतिम गाँव नहीं, भारत माँ के प्रथम गाँव है। VVP (VIBRANT VILLAGES PROGRAM) PHASE 1 -2 के अंतर्गत 4121 गाँवों के विकास के लिए लगभग 11639 करोड़ का बजट निर्धारित किया है जिसके द्वारा मौसम अनुकूल सड़क (ALL WEATHER ROAD), सौर उर्जा, मोबाइल कनेक्टिविटी, शिक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यटन का ढांचा खड़ा किया जा रहा है। 2023 में लालकिला के मैदान में 600 सीमावर्ती गाँवों के सरपंचों की सहभागिता ने सीमा एवं दिल्ली का संगम कर दिया है।

अपने पंच प्रण के संकल्प में भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आह्वान भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। इसका अनुपालन करते हुए ऑपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति एवं भारतीय स्वाभिमान में वृद्धि के अनेक प्रयास हुए हैं। IPC, CRPC की धार्यें अब भारतीय न्याय संहिता हो गई है। राजपथ अब कर्तव्यपथ, 7 रेस कोर्स रोड- 7 लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री कार्यालय - सेवा तीर्थ एवं राजभवन - लोकभवन हो गए हैं। CDS की नियुक्ति ने तीनों सेनाओं में समन्वय किया है। नेवी का प्रतीक चिन्ह अब ब्रिटिश दासता का स्मरण नहीं छत्रपति शिवाजी का स्मरण कराता, तिरंगे में अष्टकोणीय चिन्ह के साथ शिवाजी की राजमुद्रा से अंकित एवं वेद मंत्र "शं नो वरुणः" एवं अशोक स्तम्भ का स्मरण कराता है। गणतंत्र दिवस के पश्चात् सेना द्वारा आयोजित बीटिंग रिट्रीट (BEATING RETREAT) परेड में अब अंग्रेजी धुन नहीं प्रसिद्ध गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर द्वारा रचित देशभक्ति गीत "ए मेरे वतन के लोगों" ने स्थान ले लिया है। सेना में महिला सहभागिता, सैनिक स्कूलों में वृद्धि एवं अग्निवीर योजना से सुरक्षा तंत्र में समाज की सहभागिता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ऐतिहासिक सुरक्षा के प्रति किए गए निर्णय सदैव स्मरण किए जाएंगे। राष्ट्र की संप्रभुता, आर्थिक विकास, शांति सभी के लिए सुरक्षा अनिवार्य शर्त है। सुरक्षा के प्रति किए गए उपायों का ही परिणाम है कि आज देश गरीब कल्याण, ढांचगत एवं आर्थिक विकास कर अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए विश्व में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना रहा है। भारत सुरक्षा के प्रति सजग रहते हुए 2047 तक "विकसित भारत" के अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो, यह सभी नागरिकों का संकल्प बनना चाहिए।

(राष्ट्रीय सुरक्षा संकटन महामंत्री, भाजपा)

'आई लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर और हरे रंग का झंडा, मस्जिद पर बुलडोजर चलने के दौरान हॉल में मिला ये सामान



आर्यावर्त संवाददाता

संभल। यूपी के संभल के नखासा थाना पुलिस ने गांव कसेरुआ में शनिवार को सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद मुस्तफा कादरी के ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान मिले आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और झंडे के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने मस्जिद के मुतवल्ली जाकिर समेत इसी गांव के आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

शनिवार को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी इस दो मंजिला मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस तैनात रही थी। रविवार को नखासा थाने के उप निरीक्षक अरुण कुमार की ओर से दर्ज कराई गई इस रिपोर्ट के मुताबिक, अरुण कुमार मय हमराह कॉस्टेबल शुभम कुमार, अजय कुमार, राजन पंवार, विनय वर्मान के साथ गांव कसेरुआ में अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की दृष्टी में गए थे।

इसमें कोई व्यक्ति न हो, इस बात को मुहमईन करने के लिए भवन के अंदर गए और निरीक्षण किया। मस्जिद की सबसे ऊपरी मंजिल में बने मुख्य हॉल में रखे तख्त पर गढ़े के नीचे 49 पोस्टर मिले, जिन पर आई लव मोहम्मद प्रिंट हुआ है। हरे

रंग का एक झंडा भी मिला, जो पाकिस्तानी झंडा प्रतीत हो रहा है। इसे कब्जे में लिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में मुतवल्ली जाकिर, तसलीम, जाकिर हुसैन, भूरे अली, शारफुद्दीन, दिल शरीफ, मोहब्बत अली, नन्हें के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

गैर जमानती अपराध, तीन वर्ष कारावास या जुर्माना, दोनों भी संभव

कानून के जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, 2023 की धारा 353 (2) के तहत वह कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह गैर जमानती अपराध है।

कसेरुआ में 70 फीसदी ध्वस्त हो चुकी है मस्जिद

संभल। गांव कसेरुआ में मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रविवार को भी चली। बुलडोजर और क्रेन के माध्यम से कार्रवाई होती रही। प्रशासन के मुताबिक, करीब 70 फीसदी मस्जिद का निर्माण ध्वस्त हो गया है। एक-दो दिन में निर्माण को

पूरी तरह से ढाकर जमीन अतिक्रमण से मुक्त करा दी जाएगी। दरअसल, गांव में राजस्व अभिलेखों के अनुसार, गाटा संख्या 409 कब्रिस्तान की जमीन है। इसी जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया। शिकायत के आधार पर प्रशासन ने सुनवाई की। इसके बाद कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया।

तहसीलदार ने बताया कि सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। इसके चलते कार्रवाई की गई। शनिवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई, जो रविवार को पूरे दिन जारी रही। करीब 70 फीसदी निर्माण ध्वस्त हो गया है। एक दो-दिन में निर्माण पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और जमीन कब्जा मुक्त करा दी जाएगी। वहीं, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जायजा लिया। फोर्स भी तैनात रही। ट्रैक्टर-डाली और डंपरों से मलबा हटवाया गया।

डरकर नहीं बैठें, बल्कि उच्च न्यायालय जाएं, मिलेगा इंसाफ : सपा सांसद

गांव कसेरुआ में मस्जिद को हटाने की कार्रवाई के दूसरे रविवार को सपा के सांसद जियाउर्रहमान बर्क



ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों को बताया कि करीब 150 वर्षों से यह मस्जिद है, इस तरह के कुछ प्रमाण हैं। वक्फ बोर्ड में 1984 में यह दर्ज है। वक्फ ट्रिव्यूलन बोर्ड में यह प्रकरण चल भी रहा है।

बावजूद इसके सुनवाई कर ली गई है, जबकि अधिकार ही नहीं हैं। बर्क ने कहा कि सांसद होने के नाते कानूनी दायरे में रहकर अपने लोगों की लड़ाई में लड़ेंगे। धार्मिक स्थलों से कोई खिलवाड़ नहीं करने देंगे। गलत काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा।

सांसद ने लोगों से भी आह्वान किया कि डरकर नहीं बैठें, जागरूक बनें। गलत आवाज के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएं। कई बार बाद में उच्च न्यायालय से इंसाफ मिलता है। सांसद ने मस्जिद में हर झंडा मिलने पर हई कार्रवाई को लेकर हुए सवाल के जवाब में कहा कि हमारा मजहबी झंडा हरे रंग का होता है।

ईद मिलादुन्बी के मौके पर इसका उपयोग होता है। दूसरे देशों में जहां भी मुसलमान रह रहे हैं, वहां भी इसका प्रयोग में लाया जाता है। इसे बांग्लादेश, या पाकिस्तान का झंडा कहना गलत है।

अधिकारियों को पता है कि वह गलत कर रहे हैं, इसलिए डायवर्ट करना चाहते हैं लेकिन कामयाबी नहीं

सामान चोरी कर दुकान में तालाबन्दी का आरोप

जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र में फास्ट फूड की दुकान संचालित करने वाले एक दुकानदार ने दुकान से नकदी और सामान चोरी किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। जफराबाद थाना क्षेत्र के नाथपुर गांव निवासी त्रिलोकी नाथ प्रजापति ने थाना लाइन बाजार में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि वह पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से लाइन बाजार क्षेत्र में फास्ट फूड की दुकान संचालित कर रहे हैं। दुकान से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद एक व्यक्ति द्वारा लगातार दुकान खाली कराने और जान से मारने की धमकी दी जाती रही है। आरोप है कि 3 जून की रात लगभग 11 बजे उसकी दुकान से गैस सिलेंडर, सीसीटीवी कैमरा सेट, अन्य सामान तथा दुकान में रखी लगभग 75 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली गई। अगले दिन दुकान खोलने पर चोरी की जानकारी हुई।

मिलेगी। ताकत के बल पर यदि गलत कार्रवाई करेगे, तो आने वाले समय में खासियत भुगतान पड़ेगा। देश में बढ़ती महंगाई पर सांसद ने कहा कि महंगाई के दौरान सरकार को टैक्स समझे कर देने चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिले।

असंवैधानिक तरीके से की बुलडोजर कार्रवाई : सपा विधायक असमोली विधानसभा क्षेत्र की विधायक पिंकी यादव ने गांव कसेरुआ में मस्जिद हटाने की कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया है। विधायक ने एक्स पर लिखा कि सरकार के इशारे पर प्रशासन ने असंवैधानिक तरीके से मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की है, जो पूर्णतया गलत है।

प्रकरण की जानकारी के लिए प्रशासन के अधिकारियों को फोन किए लेकिन बात नहीं की गई। स्टैन्डो ने फोन रिसीव किया। आगे लिखा कि भाजपा ने बुलडोजर को अपनी गैरकानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया है।

मुसलमान, अन्य अल्पसंख्यक पिछड़े और दलित इनके निशाने पर हैं। पूर्व में राया बुजुर्ग, मुबारकपुर बंद और ऐंचोड़ा कंबोह में भी गलत कार्रवाई प्रशासन कर चुका है। हम इस तरह की कार्रवाई की निंदा करते हैं।

चोरी से शुरू हुआ जुर्म का सफर, 4 एफआईआर, गोरखपुर के टॉप-10 बदमाशों की सूची में शामिल था भानु

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। अयोध्या में एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में मारा गया बदमाश भानु प्रताप सिंह एक दशक से खोफ का पर्याय बना हुआ था। बेलघाट थाना क्षेत्र के विधानापर गांव का रहने वाला भानु की पुलिस व एसटीएफ की टीम ने कई बार घेराबंदी की लेकिन हर बार वह चकमा देकर बच निकलता था। वर्ष 2023 में बांसगांव कस्बे के पास ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को गोली मारकर रुपये लूटने के बाद जिले की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। एसएफपी ने बदमाश पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ में भानु की मौत होने की सूचना मिलने के बाद गांव में सन्नाटा है। स्वजन शव लेने अयोध्या पहुंच गए हैं।

भानु प्रताप सिंह गांव के किसान मानसिंह का पुत्र था। तीन भाइयों में वह मंझला था। बड़े भाई सबल और छोटे भाई धनंजय बाहर रहकर नौकरी करते हैं। भानु की शादी नहीं हुई थी। गांव के लोगों के अनुसार उसके पिता मानसिंहलाल के चर्चित पहलवान रहे हैं और वर्तमान में खेती-किसानी कर जीवनयापन कर रहे हैं।

गांव के लोगों ने बताया कि 10 वर्ष पहले तक भानु का गांव में आना-

युवती का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप

जौनपुर। बक्शा थाना क्षेत्र में एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण व मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता सुलतानपुर के एक गांव की रहने वाली है। पीड़िता ने बक्शा थाने में लिखित तहरीर दी है। पीड़िता ने बताया कि वह आर्केस्ट्रा में काम करती है, जहां उसकी मुलाकात जौनपुर के लाइन बाजार निवासी अजीत शर्मा से हुई। दोनों साथ काम करते थे और उनकी बातचीत होती रहती थी। अजीत शर्मा ने उससे शादी का वादा कर बार-बार शारीरिक संबंध बनाए और उसका शारीरिक शोषण किया।



जाना था, लेकिन धीरे-धीरे उसका झुकाव अपराधिक गतिविधियों की ओर बढ़ता गया। इसके बाद उसने घर से दूरी बना ली। परिवार के लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से उसका घर से कोई नियमित संपर्क नहीं था।

पुलिस अभिलेखों के अनुसार बेलघाट थाने में वर्ष 2013 में भानु पर पहला मुकदमा चोरी का दर्ज हुआ। इसी वर्ष उसके विरुद्ध हत्या का भी मुकदमा कायम हुआ। इसके बाद उसके अपराधों का सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया। वर्ष 2016 में उस पर गैसटर एक्ट की कार्रवाई हुई।

गोरखपुर पुलिस के रिकार्ड में उसके खिलाफ 41 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अन्य जिलों में दर्ज मामलों का व्योम जुटाया जा रहा है। वह बेलघाट

नवविवाहिता की हत्या में पति को 10 साल की कैद

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के भिजरा गांव में एक विवाहिता को सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसका मायका दहेज के 'दानवों' की 5 लाख रुपये की डिमांड पूरी नहीं कर सका। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी पति दिनेश पटेल को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी आधी राशि बिलखती मां को दी जाएगी। मइयाई के बारी गांव की रहने वाली बदहवास मां कमलावती ने अपनी बेटी रेनु की डोली 21 नवंबर 2017 को दिनेश

पटेल के घर बड़े अरमानों के साथ भेजी थी। मां ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान-दहेज दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह अपनी लाडली को ससुराल नहीं, बल्कि सीधे मौत के कुएं में धकेल रही है। शादी के कुछ दिन बीतते ही पति दिनेश और दोनों जेठानियों के सिर पर 5 लाख रुपये के केश का भूत सवार हो गया। रेनु को दिनेश-रात नकरीय यातनाएं दी जाने लगीं, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा गया। 4 मार्च 2020 की सुबह जब मायके वाली के फोन की घंटी बजी, तो उनके पैरों तले जमीन बिलख गई। गांव के एक शख्स ने कांपती आवाज में बताया कि 'आपकी बेटी को ससुराल वालों ने जान से मार डाला है।

भाई के मौत खबर सुनकर वृद्ध ने भी दम तोड़ा



आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। शाहगंज थाना क्षेत्र के परासन गांव में अपने बीमार चचेरे बड़े भाई का हालचाल लेकर लौट रहे एक वृद्ध की नाइं में गिरने से मौत हो गई है। इस घटना की जानकारी जब मृतक के भाई को मिली तो गहरा

सदमा लगने से कुछ घंटों के बाद उनकी भी मौत हो गई। उक्त गांव निवासी 70 वर्षीय राम नारायण प्रजापति रविवार को अपने 85 वर्षीय बड़े चचेरे भाई राम देवर के बीमार होने की जानकारी मिलने पर उनके घर हालचाल लेने गए हुए थे। देर शामग्राम नारायण अपने भाई से मिलने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। जब वह अपने गांव पहुंचे तो वहां मौजूद स्थित एक गहरे गड्ढे के पास उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सिर के बल उसमें गिर पड़े बताया गया कि गड्ढे में दलदल भरा हुआ था, जिससे वह

बाहर नहीं निकल सके और उनकी घुटने से मौत हो गई। देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंचे तो परिवजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद राम नारायण का शव गड्ढे में मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने वृद्ध की लाश को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर रात जब राम नारायण की मौत की जानकारी उनके बीमार चचेरे भाई को मिली तो वह गहरे सदमे में आ गए। परिवजनों के मुताबिक, खबर सुनते ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें हृदयाघात जैसा दौरा पड़ा। परिवार के लोग उपचार की व्यवस्था कर पाते, उससे पहले ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। एक ही परिवार में कुछ घंटों के भीतर दो मौतों से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

दाढ़ी बढ़वाई, टोपी पहनाया... शारीरिक संबंध बनाए फिर किया ब्लैकमेल, महिला जिम ट्रेनर ने कारोबारी के बेटे का कैसे बदला धर्म?

आर्यावर्त संवाददाता

शामली। यूपी के शामली जिले में एक युवक के कथित धर्मांतरण और जबरन निकाह कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जिले के बड़े देवा कारोबारी के इकलौते बेटे को महिला जिम ट्रेनर चांदनी कुरेशी ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर धर्मांतरण करवाकर हिंदू से मुस्लिम बनाया। बाद में दिल्ली ले जाकर युवक के निकाह कर लिया। पीड़ित के पिता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवती और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले को जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।



केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बेटे आयुष मलिक को सुनियोजित तरीके से प्रेम संबंधों में फंसाकर उसका धर्मांतरण कराया गया। परिवजनों का दावा है कि करीब पांच वर्ष पहले आयुष की मुलाकात चांदनी कुरेशी नामक युवती से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां

बढ़ीं। परिवार का आरोप है कि युवती और उसके परिवजनों ने आयुष को अपने प्रभाव में लेकर उसे ब्लैकमेल किया और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दवाव बनाया। आरोप है कि आयुष को दिल्ली ले जाकर एक मस्जिद में कथित रूप से निकाह कराया गया। परिवजनों का यह भी दावा

है कि युवक का खतना कराया गया और उसे कलमा पढ़ाकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। आरोप है कि मुस्लिम लड़की ने आयुष के शारीरिक संबंध बनाए और उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। बताया जाता है कि वीडियो बनाने के बाद पूरे परिवार को ब्लैकमेल किया जाने लगा।

युवती का भाई भी शामिल

मामले में यह आरोप भी सामने आया है कि चांदनी कुरेशी का भाई आयुष के संपर्क में था और उसने उसे पाकिस्तान के इस्तामिक वक्ता डॉक्टर इसरार अहमद के वीडियो देखने के लिए प्रेरित किया था। परिवार का कहना है कि इसके बाद धीरे-धीरे युवक की धार्मिक सोच में

बदलाव आया और वह दाढ़ी बढ़वा व टोपी लगाकर दुकान पर बैठने लगा।

बीते शनिवार को पुलिस ने देवराज की शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर चांदनी कुरेशी और उसके पिता इस्लाम कुरेशी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है और विभिन्न पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। बताया जाता है कि युवती पहले फिजियोथैरेपी सेंटर में काम करती थी, लेकिन बाद में जब आयुष जिम जाने लगा तो वह उसी जिम में जिम ट्रेनर बड़ी। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने चर्चा का माहौल है और पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

डायरिया रोकें अभियान की तैयारियों पर चर्चा

निजी अस्पताल बनाएं ओआरएस कॉर्नर : सीएमओ

'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम के तहत पब्लिक प्राइवेट इंटरफेस की बैठक

आर्यावर्त संवाददाता

श्रावस्ती। डायरिया रोकथाम और प्रबन्धन में निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की भूमिका पर विचार-विमर्श को लेकर सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पब्लिक प्राइवेट इंटरफेस) की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कुमार सिंह ने जनपद में शुरू होने वाले डायरिया रोकें अभियान की तैयारियों पर चर्चा की और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों से कहा कि वह अपने-अपने अस्पताल में जल्द से जल्द



ओआरएस कॉर्नर की स्थापना करें। स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में पापुलेशन सर्वेसिंग इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनयू (KENVUE) के सहयोग से आयोजित बैठक में सात निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने भाग

ले लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर (डीसीपीएम) राकेश गुप्ता ने डायरिया रोकें अभियान की कार्ययोजना साझा की। पीएसआई इंडिया के पंकज पाठक ने 'डायरिया

से डर नहीं' कार्यक्रम की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। डायरिया रोकें अभियान में निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भूमिका पर भी चर्चा की। अपर शोध अधिकारी (एआरओ) सुरेश यादव ने बैठक में आंकड़ों के संकलन एवं रिपोर्टिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने पर चर्चा की। एआरओ ने सुझाव दिया कि निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से डाटा संकलन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप साझा किया जाये। बैठक में आईसीसी सामग्री के प्रदर्शन एवं ओआरएस कॉर्नर की स्थापना पर भी चर्चा हुई। सभी निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा पीएसआई इंडिया के सहयोग से अपने-अपने संस्थानों में ओआरएस कॉर्नर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई। अंत में सभी प्रतिभागियों ने डायरिया रोकें अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

संस्था के स्थापना दिवस पर मेधावियों का सम्मान

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। सिकरारा क्षेत्र के भर्भौरी स्थित माता प्रसाद आदर्श शिक्षण संस्थान का 34वां स्थापना दिवस सोमवार को मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय व महाविद्यालय स्तर के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य वृद्धेश सिंह प्रिंसू रहे। मुख्य अतिथि ने पीजी कक्षाओं से लेकर प्ले-ग्रुप तक के विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। बोर्ड परीक्षा में विद्यालय स्तर पर हाईस्कूल एवं इंटर की छात्रा दिव्यांशी यादव एवं शशी सिंह को साइकिल भेंट की गई। इसी प्रकार कक्षा 9 एवं 11 में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छात्रा आर्या पाठक तथा छात्र उज्ज्वल सिंह को साइकिल देकर सम्मानित किया गया। जूनियर कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं



को घड़ी प्रदान की गई। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को साइकिल तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को घड़ी पुरस्कार स्वरूप दी गई। विद्यालय के प्रबंधक प्रो. समर बहादुर सिंह ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर संस्थान एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विशिष्ट अतिथि लोक

सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के पूर्व सदस्य प्रो. आर.एन. त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों का मनोबल बढ़ता है और जागरूक होते संस्थान के संचालक डॉ. विजय बहादुर सिंह ने बताया कि कुल 10 छात्र-छात्राओं को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर साइकिल प्रदान की गई। अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजबहादुर यादव ने संचालन दीपक सिंह चवेल ने किया।

सब्जी से फल तक... फैटी लिवर के लिए सबसे अच्छे फूड्स कौन से हैं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया

फैटी लिवर की समस्या को अक्सर लोग मोटापे से जोड़ते हैं लेकिन असल में ये समस्या किसी भी बॉडी वेट वाले को हो सकती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में दी गई डिटेल के मुताबिक, कई बार इसमें शुरुआती लक्षण भी पता नहीं चलते हैं। इस समस्या से बचाव और रिकवर करने के कुछ हेल्दी

फूड्स को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए।



फैटी लिवर की समस्या कम उम्र में ही देखने को मिलने लगी है। सीजीएच जनरल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों को फैटी लिवर के साथ-साथ डायबिटीज या प्रोडायबिटीज की समस्या है उनमें किसी भी वजह से मृत्यु को खतरा ज्यादा होता है। जरूरी है कि रोजाना व्यायाम किया जाए और सही आहार लें। न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया नारंग ने फैटी लिवर वालों के लिए सबसे बेस्ट सब्जी से लेकर सबसे अच्छे अनाज तक अलग-अलग फूड्स के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको भी फैटी लिवर की समस्या है तो इन फूड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

फैटी लिवर दो तरह का होता है नॉन-एल्कोहॉलिक और अल्कोहॉलिक।

इसकी मुख्य वजह होती है बहुत ज्यादा मात्रा में फैट वाली चीजें लेना या फिर ज्यादा अल्कोहल का सेवन करना। इस आर्टिकल में जानेंगे फैटी लिवर वालों के लिए सबसे अच्छे फूड्स कौन से होते हैं और आपको कौन सी चीजों से परहेज करना चाहिए।

सबसे अच्छा फल

न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया नारंग कहती हैं कि फैटी लिवर के लिए सबसे अच्छा फल है ब्लूबेरी। हेल्थ लाइन के मुताबिक, ब्लूबेरीज डीएनए डैमेज से बचाव करती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ब्रेन फंक्शन को मॉडरेट करने में हेल्पफुल होने से लेकर इसमें एंटीडायबिटिक इफेक्ट्स भी होते हैं।

यही वजह है कि ये लिवर के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। ब्लूबेरीज लो कैलोरी फूड है और इसमें हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 150 ग्राम ब्लूबेरी में डेली जरूरत का 13 प्रतिशत फाइबर, 14 प्रतिशत विटामिन सी, और 24 प्रतिशत विटामिन के होता है। इसमें 85 प्रतिशत पानी पाया जाता है।

सबसे अच्छी सब्जी

फैटी लिवर की समस्या है तो सबसे अच्छी सब्जी आपके लिए ब्रोकली है। हेल्थ लाइन के मुताबिक भी ब्रोकली आपके लिवर के लिए फायदेमंद होती है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ब्रसेल्स स्प्राउट्स, केल, फूलगोभी और पत्तागोभी (केबेज) शामिल कर सकते हैं।

सबसे अच्छा आटा

न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया नारंग के मुताबिक, फैटी लिवर वालों के लिए सबसे अच्छा आटा है जौ का आटा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक, जौ का आटा शरीर में ग्लूकोज कंट्रोल करने के साथ ही फैटी लिवर को भी कम कर सकता है।

सबसे अच्छे सीड्स

फैटी लिवर है तो आपको अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी को शामिल करना चाहिए। अलसी के बीज गुड फैट्स से भरपूर होते हैं। इसके अलावा भी इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये आपके लिवर के साथ ही ओवरऑल हेल्थ को कई फायदे पहुंचाते हैं।

सबसे अच्छे नट्स

जिन लोगों को फैटी लिवर की समस्या है उनके लिए न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया नारंग ने सबसे अच्छे नट्स बताए हैं वॉलनट्स यानी अखरोट। नट्स में गुड फैट्स अच्छी मात्रा में होते हैं। 2019 में 24 हजार लोगों पर की गई एक स्टडी के मुताबिक, जो लोग मेवे का ज्यादा सेवन करते हैं उनमें एनएलएफडी (NALFD) का खतरा कम होता है।

सबसे अच्छी ड्रिंक

सोनिया नारंग कहती हैं कि सबसे अच्छी ड्रिंक फैटी लिवर वालों के लिए ब्लैक कॉफी है। इसे जरूर पीना चाहिए। ध्यान रखें इसमें शुगर एड नहीं

करनी है। पबमेड में छपी जानकारी के मुताबिक, प्रायोगिक अध्ययनों से पता चलता है कि कॉफी का सेवन करने से लिवर में फैट और कोलेजन के जमाव को कम करने में मदद मिलती है।

किन चीजों से करें परहेज

हाई फैट चीजें जैसे समोसा, पकोड़े, फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट से दूरी बनाएं। शराब लिवर के लिए बिल्कुल जहर के बराबर मानी जाती है। जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स या मैदा से बनी कोई भी चीज अर्वाइड करें।

मीठी चीजों जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पैकड

फूड,

मिठाइयां या

किसी भी

तरह से शुगर

को अर्वाइड करना

चाहिए।

शुगर के साथ ही ज्यादा

नमक वाली चीजें जैसे चिप्स, नमकीन

और रोस्टेड साल्टी

स्नेक्स से दूरी

बनाएं।



डेडलिफ्ट के करते हुए रकुलप्रीत सिंह को हुई थी इंजरी, जानें इसे करते हुए किन बातों का रखें ध्यान



फिटनेस के लिए डेडलिफ्ट एक्सरसाइज को काफी अस्परदार माना जाता है। लेकिन इसे करने में की गई एक भी गलती भारी पड़ सकती है। हाल ही में एक शो पर एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने बताया कि 80 किलो डेडलिफ्ट करते हुए उनकी स्लिप डिस्क खिसक गई है, जिसकी वजह से उन्हें करीब 40 दिन तक बेड रेस्ट करना पड़ा था। इस दौरान न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी उन्हें काफी तकलीफ हुई थी। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि डेडलिफ्ट करना आसान नहीं है।

एक्सपर्ट के मुताबिक डेडलिफ्ट करते समय सही पोस्चर, नियंत्रित मूवमेंट और अपनी क्षमता के अनुसार वजन चुनना बेहद जरूरी होता है। जल्दबाजी में भारी वजन उठाने या गलत तकनीक अपनाने से कमर, रीढ़ और मांसपेशियों पर एक्सट्रा दबाव पड़ सकता है। इस आर्टिकल में चलिए जानते हैं कि डेडलिफ्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

डेडलिफ्ट कैसे की जाती है?

डेडलिफ्ट एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए जमीन पर रखे डंबल को उठाकर शरीर को सीधा खड़ा किया जाता है। इस दौरान आपको अपने पैरों और कंधों की चौड़ाई जितना खोलकर खड़े होना है और डंबल को पैरों के करीब रखना है। इस दौरान काफी ज्यादा भारी वजन उठाना होता है। कमर और रीढ़ को हड्डी पर दबाव न पड़े। इसलिए इस दौरान सेफ्टी बेल्ट लगाना जरूरी होता है। कमर को सीधा रखते हुए घुटनों को मोड़ें और दोनों हाथों से बार को मजबूती से पकड़ें। इसके बाद एडिडों पर दबाव डालते हुए पैरों और कूल्हों की ताकत से वजन को ऊपर उठाएं। इस दौरान शरीर पूरी तरह सीधा होना चाहिए। इसी पोजीशन में

कुछ सेकंड रुकें और वजन को वापस रखें।

डेडलिफ्ट करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना इस एक्सरसाइज के दौरान सबसे जरूरी होता है। रकुलप्रीत ने बताया कि उन्होंने 80 किलो वजन उठाते समय सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी थी, जिसकी वजह से ही उन्हें इंजरी हुई थी। ऐसे में आपको भी कुछ बातों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। जिसमें पहला है सेफ्टी बेल्ट का यूज। इसके अलावा डेडलिफ्ट करते समय सबसे जरूरी है कि आपको रीढ़ की हड्डी न्यूट्रल पोजीशन में रहे और पीठ गोल न हो। शुरुआत में हल्के वजन से प्रैक्टिस करें और सही तकनीक सीखने के बाद ही वजन बढ़ाना चाहिए। एक्सरसाइज के दौरान कोर मसल्स को टाइट रखना जरूरी होता है। अचानक झटके से वजन उठाने से बचना चाहिए। अगर पहले से कमर, गर्दन या घुटनों से जुड़ी कोई समस्या है तो एक्सपर्ट की सलाह के बिना इस एक्सरसाइज को करने से बचें।

डेडलिफ्ट के क्या फायदे होते हैं?

डेडलिफ्ट पूरे शरीर की ताकत बढ़ाने वाली कंपाउंड एक्सरसाइज मानी जाती है। यह पीठ, कूल्हों, जांघों, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और कोर मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करती है। नियमित रूप से सही तरीके से डेडलिफ्ट करने से बॉडी पोस्चर बेहतर हो सकता है, बैलेंस और स्टैमिना बढ़ सकता है। साथ ही रोजमर्रा के कामों में शरीर की कार्यक्षमता में सुधार आता है। इसके अलावा यह कैलोरी बर्न करने और मसल्स ग्रोथ में भी सहायक मानी जाती है।

बार-बार हाथ धोते हैं फिर भी बीमार पड़ते हैं? ये गलतियां हो सकती हैं वजह

हाथ धोना हमारे डेली रूटीन का एक अहम हिस्सा है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग हाथ धोने में कुछ आम गलतियां कर देते हैं, जो बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। चलिए जानते हैं स्टडी के मुताबिक, हाथों का सही से न धोना कौन-कौन सी समस्याएं ला सकते हैं। साथ ही किन गलतियों को करने से बचना चाहिए।

हाथों में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पैदा होते हैं। क्योंकि हाथों का इस्तेमाल हम हर जगह और हर काम के लिए करते हैं। ऐसे में समय-समय पर हाथ धोना जरूरी बताया गया है। लेकिन क्या सिर्फ हाथ धोना बैक्टीरिया को कम कर देता है? नहीं... ऐसा नहीं है। आज भी लोग हाथ धोते समय कुछ ऐसी आम गलतियां करते हैं, जिससे हाथ पूरी तरह से साफ नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि हाथ धोने के बाद भी कई लोग और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि गलती कहाँ हो रही है।

दरअसल, समस्या हाथ धोने की आदत में नहीं बल्कि उसे गलत तरीके से करने में हो सकती है। बहुत कम समय तक हाथ धोना, उंगलियों के बीच और नाखूनों की सफाई को नजरअंदाज करना या हाथ धोने के तुरंत बाद दूषित सतहों को छू लेना जैसी गलतियां संक्रमण के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। चलिए जानते हैं हाथ धोने का सही तरीका और समय क्या है।

हाथ सोच से ज्यादा फैला सकते हैं संक्रमण

ज्यादातर लोग मानते हैं कि संक्रमण मुख्य रूप से खांसने, छींकने या भीड़भाड़ वाली जगहों के जरिए फैलता है। लेकिन कई सामान्य बीमारियां गंदे हाथों के जरिए भी फैलती हैं। जब हम दूषित हाथों से अपने मुँह, नाक, भोजन या आसपास की चीजों को छूते हैं, तो संक्रमण आसानी से शरीर में पहुंच सकता है। सामान्य सर्दी-जुकाम, फ्लू, डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां इसी रास्ते से फैल सकती हैं। इसके बावजूद अक्सर लोग सिर्फ हाथों के साफ दिखने को ही स्वच्छता मान लेते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट और स्टडी के अनुसार सही तरीके से हाथ धोने की आवृत्ति संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम कर सकती है। आंकड़ों के मुताबिक, नियमित और सही हैंडवॉशिंग से डायरिया के मामलों में 23 से 40 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। वहीं कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में डायरिया का खतरा 58 प्रतिशत तक घट सकता है। इसके अलावा सर्दी-जुकाम जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों के मामलों में भी 16 से 21 प्रतिशत तक कमी देखी



गई है।

क्या आप पर्याप्त समय तक हाथ धोते हैं?

कई लोग हाथ धोते समय केवल कुछ सेकंड तक पानी से हाथ साफ कर लेते हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता। विशेषज्ञों का कहना है कि हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह रगड़कर धोना चाहिए। हाथ धोते समय हथेलियों के साथ-साथ हाथों की पीठ, उंगलियों के बीच की जगह, पोर, अंगुठे, उंगलियों के सिरे और कलाई को भी अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। ये वे हिस्से हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।

इसके अलावा हाथ धोने के बाद उन्हें अच्छी

तरह सुखाना भी जरूरी है। गीले हाथों पर कीटाणु आसानी से चिपक सकते हैं और फैल सकते हैं। वहीं लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे गीले तौलिये भी दोबारा संक्रमण का कारण बन सकते हैं।

हाथ कब-कब धोना जरूरी है?

हाथ धोने का सही समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी सही तकनीक। खाने खाने से पहले या बनाने से पहले, शौचालय का उपयोग करने के बाद, खांसने या छींकने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद, कूड़ा छूने के बाद और जानवरों या सार्वजनिक स्थानों की ज्यादा छुई जाने वाली सतहों को छूने के बाद हाथ जरूर धोने चाहिए।

अगर 10% का मिला हाइक, तो ₹12 लाख से ₹50 लाख तक की सैलरी पर ये होगा असर

सैलरी में 10% बढ़ोतरी सुनने में भले ही बड़ी राहत लगे, लेकिन इसका पूरा फायदा कर्मचारियों को नहीं मिलता। आय बढ़ने के साथ टैक्स और अन्य कटौतियां भी बढ़ जाती हैं, जिससे हाथ में आने वाली रकम कम हो जाती है।



नौकरीपेशा लोगों के लिए सैलरी बढ़ना हमेशा खुशखबरी होती है, लेकिन हर बढ़ी हुई रकम सीधे जेब में नहीं पहुंचती। नई टैक्स व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ टैक्स देनदारी भी बढ़ जाती है, जिससे सैलरी हाइक का एक हिस्सा टैक्स में चला जाता है। खासकर 12 लाख रुपये से 50 लाख रुपये सालाना कमाने वाले कर्मचारियों के लिए 10% वेतन बढ़ोतरी का वास्तविक फायदा अलग-अलग हो सकता है। आइए समझते हैं कि सैलरी बढ़ने के बाद हाथ में कितनी अतिरिक्त रकम बचती है।

किसी कर्मचारी की सैलरी बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि उसकी पूरी अतिरिक्त आय उसके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। आय बढ़ने के साथ टैक्स स्लेब के अनुसार टैक्स भी बढ़ता है। इसके अलावा बेसिक सैलरी से जुड़ी कुछ कटौतियां, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भी बढ़ सकती हैं। इसका असर टेक-होम सैलरी पर

पड़ता है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, लेकिन इसके बावजूद आय बढ़ने पर टैक्स देनदारी भी बढ़ जाती है।

12 लाख रुपये सैलरी वालों पर सबसे ज्यादा असर

यदि किसी कर्मचारी की सालाना सैलरी 12 लाख रुपये है और उसे 10% की बढ़ोतरी मिलती है, तो उसकी आय 1.12 लाख रुपये बढ़ जाएगी। हालांकि बढ़ी हुई आय पर टैक्स देनदारी भी बढ़ेगी। मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलने के बाद भी लगभग 46,800 रुपये अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है। ऐसे में कर्मचारी के हाथ में वास्तविक फायदा करीब 73,200 रुपये ही रह जाता है।

16 लाख से 24 लाख रुपये तक की

आय पर क्या होगा असर?

16 लाख रुपये सालाना कमाने वाले कर्मचारी को 10% हाइक के बाद 1.6 लाख रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। लेकिन टैक्स कटने के बाद उसके पास करीब 1.31 लाख रुपये का वास्तविक लाभ बचेगा। वहीं 20 लाख रुपये की सैलरी वाले कर्मचारी को 2 लाख रुपये की बढ़ोतरी पर लगभग 1.52 लाख रुपये का पोस्ट-टैक्स फायदा मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की सालाना आय 24 लाख रुपये है, तो 2.4 लाख रुपये की बढ़ी हुई सैलरी में से टैक्स कटने के बाद लगभग 1.69 लाख रुपये का फायदा ही हाथ में आएगा।

ऊंची आय वालों का बड़ा हिस्सा टैक्स में जाता है

जैसे-जैसे आय बढ़ती है, टैक्स का असर भी अधिक दिखाई देता है। 30 लाख रुपये सालाना कमाने वाले कर्मचारी को 3 लाख रुपये की बढ़ोतरी पर करीब 2.06 लाख रुपये का वास्तविक लाभ मिलेगा। वहीं 40 लाख रुपये सालाना आय वाले कर्मचारी को 4 लाख रुपये की बढ़ी हुई सैलरी पर लगभग 1.25 लाख रुपये अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है। इसके बाद उसके पास करीब 2.75 लाख रुपये का फायदा बचेगा। 50 लाख रुपये सालाना कमाने वाले कर्मचारी को 5 लाख रुपये की सैलरी बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन अतिरिक्त टैक्स देनदारी करीब 2.18 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। ऐसे में उसके हाथ में वास्तविक लाभ केवल 2.18 लाख रुपये के आसपास रहेगा।

सैलरी हाइक मिलने पर केवल ग्रॉस इंक्रीमेंट देखकर खुश होने के बजाय पोस्ट-टैक्स लाभ की गणना करनी चाहिए। कर्मचारी अपने वेतन ढांचे की समीक्षा कर सकते हैं और कंपनी के जरिए उपलब्ध कॉर्पोरेट NPS जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही नई टैक्स व्यवस्था में उपलब्ध लाभों को समझकर टैक्स प्लानिंग करना जरूरी है, ताकि बढ़ी हुई सैलरी का ज्यादा हिस्सा उनकी जेब में पहुंच सके।

आपकी एसआईपी सुरक्षित है? बार-बार फेल हो रही है पेमेंट



बहुत से निवेशक मानते हैं कि एसआईपी एक बार सेट कर देने के बाद यह हर महीने अपने आप चलता रहता है। पैसा हर महीने खाते से कटता है और निवेश लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन असल में कई बार एसआईपी फेल हो जाता है और लोग इस बात को देर से समझ पाते हैं।

एसआईपी फेल होने की सबसे बड़ी वजह

अधिकतर मामलों में एसआईपी इसलिए फेल होता है क्योंकि बैंक खाते में पर्याप्त पैसा नहीं

होता। कई बार लोग दिन में बाद में पैसे डालते हैं, लेकिन तब तक ऑटो-डेबिट प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। अगर एक ही दिन कई एसआईपी कटते हैं तो समस्या और बढ़ जाती है। इससे बैंक पेनल्टी भी लग सकती है।

गलत एसआईपी सेटअप भी बनता है वजह

कई लोग सभी एसआईपी एक ही तारीख पर सेट कर देते हैं, जैसे सैलरी के तुरंत बाद। अगर उस दिन सैलरी लेट हो जाए या कोई बैंकिंग समस्या आ जाए, तो सारी एसआईपी एक साथ

फेल हो सकती हैं। इसलिए एसआईपी की तारीखें महीने में अलग-अलग रखना बेहतर माना जाता है।

मैंडेट की दिक्कत भी आम कारण

कई बार एसआईपी सही होता है लेकिन उसका बैंक बैंड में डेट पुराना या इनएक्टिव हो जाता है। बैंक बदलना, मोबाइल नंबर अपडेट करना या अकाउंट बदलने से भी बैंड में नॉटिफिकेशन को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे समस्या बढ़ जाती है।

UPI AutoPay से जुड़ी नई समस्या

2026 में UPI AutoPay सिस्टम में कुछ तकनीकी बदलावों और ट्रैफिक की वजह से भी कुछ एसआईपी पेमेंट फेल होने की शिकायतें सामने आई हैं। कई लोग नॉटिफिकेशन को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे समस्या बढ़ जाती है।

सही एसआईपी सिस्टम क्या है?

एक अच्छा एसआईपी सिस्टम बहुत सिंपल होता है। खाते में थोड़ा बफर बैलेंस रखना, एसआईपी की तारीखें फेलाना, बैंड में नॉटिफिकेशन को नजरअंदाज न करना। असल में एसआईपी में सफलता सिर्फ सही म्यूचुअल फंड चुनने से नहीं, बल्कि नियमित और सही पेमेंट मैनेजमेंट से भी मिलती है।

बीएसएनएल में नौकरी का अवसर : जनरल मैनेजर के 15 पदों के लिए जल्द सक्रिय होगा आवेदन लिंक

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने देश भर में विभिन्न पोस्टिंग/स्थान के लिए फाइनेंस और अकाउंट्स स्ट्रीम में कान्स्ट्रक्ट के आधार पर जनरल मैनेजर के कुल 15 पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीएसएनएल की ओर से जारी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 6 जून के सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 जून के सुबह 10 बजे तक तय की गई है।

ऐसे में जो पात्र उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे बीएसएनएल के ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद से तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं, जिन अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र जमा करते समय कुछ गलती हो जाती है, उनके लिए फॉर्म में त्रुटि को सुधारने का विंडो 25 जून के सुबह 10 बजे से 28 जून के सुबह 10 बजे तक सक्रिय रहेगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त

यूनिवर्सिटी/संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (सीएमए) या एमबीए (फाइनेंस) या मैनेजमेंट (फाइनेंस) में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास प्रासंगिक क्षेत्र में 3 से 15 वर्षों का अनुभव और अन्य निर्धारित पात्रता व कौशल का होना भी अनिवार्य है। आवेदकों की अधिकतम आय 50 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आयु, योग्यता और अनुभव के आधार पर प्रारंभिक स्क्रॉनिंग, समूह चर्चा और प्रस्तुति एवं इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 2,25,000 रुपये के बीच प्रति माह होगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सभी वर्ग के उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो 1,000 रुपये तय किया गया है। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि सफलतापूर्वक आवेदन शुल्क के भुगतान के बाद ही आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा।

फिलीपींस में भूकंप से दहशत: झटकों से पलभर में ढही इमारतें, चार की मौत, 200+ घायल

मनीला, एजेंसी। फिलीपींस में सोमवार को आए 8.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के पास आए इस भूकंप के बाद कई इमारतें ढह गईं और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में इमारतों को गिरते और लोग जान बचाकर भागते दिखाई दिए। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया।

भूकंप के तेज झटकों के बाद लोग घरो, स्कूलों और अस्पतालों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। कई स्कूल और यूनिवर्सिटी भवनों को



नुकसान पहुंचा है। वायरल वीडियो में देखा गया कि एक स्कूल परिसर के बाहर छात्र खुले मैदान में खड़े थे, तभी पीछे की इमारत का हिस्सा भरभराकर गिर गया। अस्पतालों में मरीजों को

तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। प्रशासन ने लोगों को समुद्र किनारे वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी। कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं भी प्रभावित हुईं।

राहत और बचाव अभियान लगातार जारी

पुलिस, सेना और राहत एजेंसियां लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जनरल सैंटोस सिटी पुलिस के

अधिकारी रॉबर्ट डैगन ने बताया कि कई इमारतें और मकान गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी नुकसान का पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया है क्योंकि बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। कई लोग मलबे में फंसे होने की आशंका हैं। सरंगाणी प्रांत के अलाबेल शहर में पुलिस स्टेशन की दीवारों में दरारें पड़ गईं। कई सड़कों पर दरारें आने से राहत कार्य में दिक्कतें भी सामने आईं।

व्या आपटरशॉक ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी?

मुख्य भूकंप के कुछ घंटों बाद 6.11 तीव्रता का आपटरशॉक भी दर्ज किया गया। इसके बाद लोग घरों में लौटने से डरने लगे। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से खुले मैदानों और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की। कई परिवार रातभर खुले आसमान के नीचे

रहने को मजबूर हो गए। प्रशासन ने स्कूलों और सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा जांच शुरू कर दी है ताकि किसी और हादसे से बचा जा सके।

व्या फिलीपींस पहले भी ऐसे बड़े भूकंप झेल चुका है?

फिलीपींस प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में स्थित है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाकों में गिना जाता है। यहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार का भूकंप हाल के वर्षों के नुकसानों से अधिक है। सरकार ने आपदा प्रबंधन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है और लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और पुनर्वास का काम शुरू

कर दिया गया है।

सुनामी में भारी नुकसान की आशंका

अमेरिकी और प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्रों के साथ-साथ स्थानीय एजेंसियों ने तटीय इलाकों में एक मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठने और भारी नुकसान की आशंका जताई है, जो अगले कई घंटों तक जारी रह सकती है। फिलीपींस में, फिलीपीन ज्वालामुखी विज्ञान और भूकंप विज्ञान संस्थान (फिवोल्क्स) ने भूकंप की तीव्रता 7.8 आंकी और संभावित नुकसानों और एक मीटर से अधिक ऊंची सुनामी लहरों की चेतावनी दी है। कई जगहों पर भवनों में दरार और कई घर गिरने की भी खबरें हैं।

जापान, इंडोनेशिया समेत इन

देशों में अलर्ट

अलजजीरा के मुताबिक, फिलीपींस के पास आए जबरदस्त भूकंप के बाद जापान ने अपने प्रशांत महासागर तट के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जापान के कुछ इलाकों में एक मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। भूकंप के बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने सुनामी का खतरा बताते हुए चेतावनी जारी की है। एजेंसी के मुताबिक, खतरनाक लहरें समुद्र तट पर स्थित द्वीप को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके बाद इंडोनेशिया से अधिक नुकसान की चेतावनी जारी की है और अपने नागरिकों को सतर्क रहने के साथ-साथ निदेशों का पालन करने की अपील की।

गाजा में इस्त्राइली हमलों में नौ फलस्तीनियों की मौत; बेन गवीर के सोशल मीडिया पोस्ट पर छिड़ा विवाद

गाजा, एजेंसी। गाजा में रविवार को इस्त्राइल के हवाई हमलों में कम से कम नौ फलस्तीनी मारे गए। फलस्तीनी रेड क्रॉस के अनुसार, दक्षिणी गाजा के खान यूनिंस शहर में एक पुलिस चौकी पर हुए इस्त्राइली हवाई हमले में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों और मृतकों को रेड क्रॉस द्वारा संचालित फील्ड अस्पताल में ले जाया गया। इसके बाद दिन में गाजा सिटी के पश्चिमी इलाके में एक वाहन पर हुए इस्त्राइली हमले में कम से कम चार और फलस्तीनियों की मौत हो गई। शिफा अस्पताल में इन मृतकों के शव प्राप्त होने की पुष्टि की है।

इन दोनों हमलों पर इस्त्राइली सेना की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। हालांकि, इस्त्राइल पहले भी कहता रहा है कि वह उन लड़ाकों को निशाना बनाता है जो उसकी सेना के लिए खतरा बन सकते हैं। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका

की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम समझौते के बाद बड़े पैमाने की लड़ाई में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद लगभग रोजाना इस्त्राइली गोलीबारी और हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच, ईरान द्वारा इस्त्राइल पर मिसाइलें दागे जाने के बाद सुरक्षा स्थिति बिगड़ने का हवाला देते हुए इस्त्राइल ने गाजा के साथ सभी सीमा पार मार्गों को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। गाजा में मानवीय सहायता की निगरानी करने वाली इस्त्राइली रक्षा एजेंसी ने इसकी जानकारी दी। इस्त्राइल के प्रधानमंत्री बेजाजिन नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक के दौरान कहा कि इस्त्राइल जल्द ही गाजा के 70 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा, 'इस समय हमारे नियंत्रण में गाजा का 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र है और जल्द ही हम 70 प्रतिशत तक पहुंच जाएंगे।' नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इस्त्राइल हमला को दोबारा हथियार जुटाने या इस्त्राइल को नुकसान पहुंचाने

की अनुमति नहीं देगा। वहीं, अमेरिका द्वारा गठित बोर्ड ऑफ पीस के प्रमुख ने पिछले महीने माना था कि युद्धविराम प्रक्रिया का अगला चरण फिलहाल रुका हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण हमला से निरस्त करने के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सहमति न बन पाना बताया गया है। एक अलग घटना में इस्त्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुरक्षा बलों की सराहना की, जिन्होंने एक हमलावर को मार गिराया था। इस्त्राइल के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें वह मृत हमलावर के शव के पास खड़े दिखाई दिए। वीडियो में बेन-गवीर ने कहा, 'हर आतंकवादी का यही अंत होगा।' बेन-गवीर हाल ही में फलस्तीनी हमलावरों के लिए मृत्युदंड लागू करने संबंधी कानून को आगे बढ़ाने की कोशिश कर चुके हैं, हालांकि इस कानून को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

'स्वाभिमानी देश मिसाइल हमले नहीं सहेंगा', ईरान पर कार्रवाई को लेकर इस्त्राइली राजदूत की दो टूक



हिजबुल्लाह ने इस्त्राइल पर हमले जारी रखे तो बेरूत के दहिया क्षेत्र में स्थित उसके कमांड सेंटर्स को कड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लेबनान में चल रही कार्रवाई और तेहरान के खिलाफ इस्त्राइल के सीधे अभियान अलग-अलग मुद्दे हैं। इस बीच सोमवार तड़के युद्धविराम पूरी तरह टूटता दिखाई दिया, जब अप्रैल में हुए संघर्षविराम के बाद पहली बार

ईरान ने इस्त्राइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। जवाब में इस्त्राइल ने ईरान के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरान के इस्फहान, तबरीज, कराज और तेहरान सहित कई शहरों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। तनाव बढ़ने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशों को भी झटका लगा है। ट्रंप लंबे समय से ईरान और इस्त्राइल के बीच तनाव

कम करने और तेहरान के साथ संभावित परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में कहा था कि दोनों पक्ष समझौते के बेहद करीब हैं और प्रतिशोध प्रयास पटरी से उतर सकता है। ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा कि इस्त्राइल ने अपना हमला किया, ईरान ने भी जवाब दे दिया। अब हमें एक और जवाबी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि लगातार प्रतिशोध का सिलसिला क्षेत्र को अंतहीन हिंसा में धकेल सकता है। रविवार शाम ईरान द्वारा उत्तरी इस्त्राइल की ओर मिसाइलों की बौछार किए जाने के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। इस्त्राइली वायु रक्षा प्रणाली ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, जिससे किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली।

हालांकि लाखों लोगों को बंकरों और सुरक्षित स्थानों में शरण लेनी पड़ी। हमलों के बाद इस्त्राइली सेना के प्रवक्ता एफ्री डेरिन ने कहा कि ईरान ने गंभीर गलती की है। वहीं इस्त्राइल के सेना प्रमुख इयाल जमीर ने कहा कि आदेश मिलते ही दुश्मन पर निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर, ईरान की इस्लामिक क्रांतिकारी गार्ड कोर ने चेतावनी दी है कि यदि इस्त्राइल या उसके सहयोगियों ने आगे कोई हमला किया तो जवाबी कार्रवाई और व्यापक होगी। संगठन ने अमेरिकी और इस्त्राइली हितों को भी निशाने पर लेने की धमकी दी। क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाते हुए इराक की शिया संगठन हिजबुल्लाह ने भी चेतावनी दी कि यदि अमेरिका सीधे संघर्ष में शामिल हुआ तो इराक और पूरे क्षेत्र में उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा।

सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाए जा रहे 5 धार्मिक ढांचे, सुरक्षा में 3000 पुलिसकर्मी तैनात, इंटरनेट बंद

नई दिल्ली, एजेंसी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सोमवार को शहर के एक प्रमुख इलाके में सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई के तहत सड़क की निर्धारित सीमा में आने वाले दो मंदिर और एक मस्जिद सहित कुल पांच धार्मिक ढांचों को हटाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बेहद सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं, जिसके तहत भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, एहतियात के तौर पर प्रशासन ने शहर के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी हैं। शहर के जगतपुरा स्थित नंदपुरी अंडरपास क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 3,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अभियान के तहत रेलवे

लाइन के समानांतर सड़क को 80 फुट तक चौड़ा किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, सड़क की निर्धारित सीमा में आने वाले पांच धार्मिक ढांचों—एक मस्जिद, दो मंदिर, एक सल्गम भवन और एक मजार को इस कार्रवाई के दौरान हटाया जाएगा। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, जयपुर उत्तर और जयपुर पूर्व पुलिस जिलों में रविवार रात 12 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। इसके साथ ही सामूहिक रूप से एसएमएस और एमएमएस भेजने की सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है। सोशल मीडिया मंचों तक पहुंच भी प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, फोन कॉल सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहेंगी। सभागीय आयुक्त वी. श्रवण कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित संचार माध्यमों के दुरुपयोग की आशंका, अफवाहों पर रोक लगाने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

सीपीए सम्मेलन में 'विकसित भारत' पर महामंथन, बिरला बोले- नीतियों से साकार होगा संकल्प

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि यहां आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) सम्मेलन में 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक नीतियों पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में आयोजित तीन दिवसीय द्वितीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र, जोन-दो सम्मेलन का उद्घाटन बिरला करेंगे।



चंडीगढ़ पहुंचने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, "इस बात पर चर्चा होगी कि हम नीतियों के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को कैसे साकार कर सकते हैं।" सम्मेलन में सीपीए भारत क्षेत्र जोन-दो के पांच राज्यों—जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब,

जागरूक समाज और जनप्रतिनिधियों की भूमिका' विषय पर विचार-विमर्श करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण तथा राज्य के संसदीय कार्य

मंत्री महिपाल ढांडा भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

सम्मेलन का समापन नौ जून को होगा, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल आशिम कुमार घोष समापन भाषण देंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सम्मेलन का उद्देश्य संसदीय सहयोग को मजबूत करना, विधायी एवं संसदीय कार्यप्रणाली से जुड़े श्रेष्ठ अनुभवों का आदान-प्रदान करना तथा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना है। बयान में कहा गया है कि यह सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अपने अनुभव साझा करने तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने संबंधी रणनीतियों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करेगा।

सीमा पर ₹142 करोड़ की जब्ती, म्यांमार-बांग्लादेश बॉर्डर समेत बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में भी तलाशी

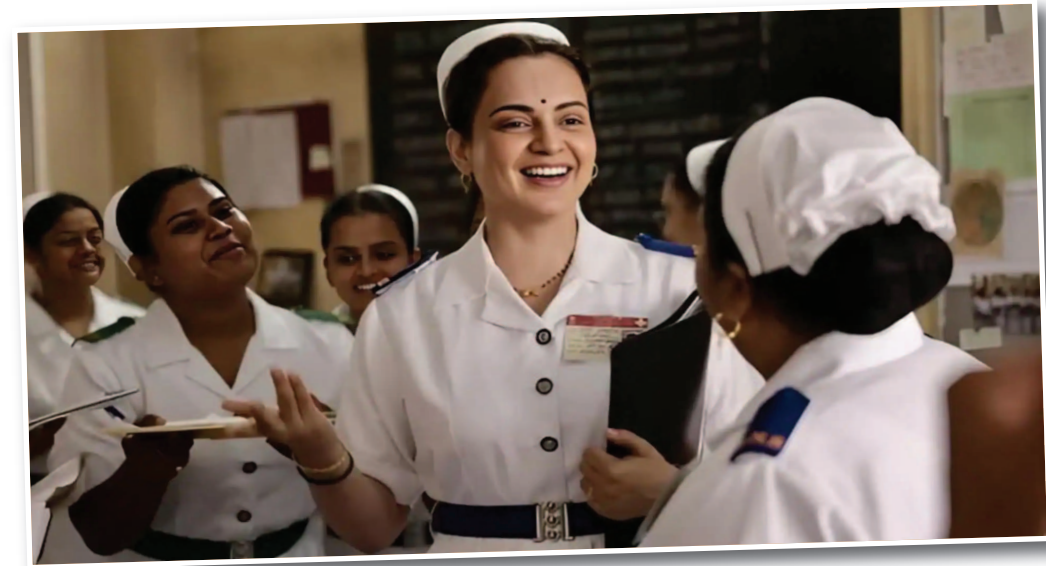


जाती थी।

ड्रग तस्करी नेटवर्क का खुलासा

अधिकारियों के मुताबिक, जांच में एक संगठित अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो भारत-म्यांमार और भारत-बांग्लादेश सीमाओं का इस्तेमाल कर रहा था। ईडी ने अब तक इस मामले में 142 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित संपत्ति (प्रोसीड्यूस ऑफ़ फ़ाइंड्स) की पहचान की है। मामले में शामिल संदिग्धों और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच जारी है।

कंगना रनौत अब नर्स बनकर दिखाएंगी दम, 12 जून को रिलीज होगी फिल्म भारत भाग्य विधाता



कंगना रनौत एक बार फिर पदों पर अपनी दमदार अदाकारी का जादू बिखरने के लिए तैयार हैं। उनकी बहुचर्चित फिल्म भारत भाग्य विधाता की रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान हो गया है। 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान कामा अस्पताल में नर्सों और मेडिकल स्टाफ के अदम्य साहस पर आधारित इस फिल्म में कंगना एक नर्स की मुख्य भूमिका निभा रही हैं। पदों पर कब दस्तक देगी भारत भाग्य विधाता, आइए जानते हैं।

कंगना की बहुप्रतीक्षित फिल्म भारत भाग्य विधाता की रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान हो गया है। सच्ची घटना पर आधारित ये थ्रिलर फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मनोज तपड़िया के निर्देशन में बनी यह फिल्म 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान कामा अस्पताल के उन अनसंग हीरोज की बहादुरी को सलाम करती है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर 400 लोगों की सुरक्षित बचाया था। फिल्म में कंगना एक नर्स की मुख्य भूमिका निभा रही हैं।

कंगना के प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स ने अपनी अगली बड़ी फिल्म भारत भाग्य विधाता का आधिकारिक पोस्टर जारी कर दिया है। फिल्म के इस पोस्टर के साथ साझा किया गए संदेश में लिखा गया, साधारण लोगों की एक असाधारण कहानी! ईंसानियत की वो दास्तां, जब डर से कहीं बड़ा हैसला नजर आया। जब जिम्मेदारी ही बलिदान बन गई, जब एकता ही सबसे बड़ा कर्तव्य बनी और साहस ने बचाई मासूम जिंदगियां। पेश है भारत के असली नायकों की अनकही कहानी।

कंगना ने कहा, हम अक्सर शोर मचाने वाली बहादुरी का जश्न मनाते हैं, लेकिन असली साहस वो होता है, जो मौके पर डटा रहे, पीछे न हटे और जिम्मेदारी उठाए। भारत भाग्य विधाता साहस, बलिदान, ईंसानियत और एकता की एक ऐसी अनकही कहानी है, जहां साधारण लोग आतंक और जिंदगी के बीच ढाल बनकर खड़े हो गए। ये देशभक्ति का सबसे शुद्ध रूप है, जहां कर्तव्य ही कर्म बन जाता है। कंगना आगे बोलें, मुझे उस कहानी का हिस्सा बनने पर गर्व है, जो उन लोगों को सलाम करती है, जिन्होंने शहर के सबसे कठिन पलों में उसे थामे रखा। मुझे दर्शकों की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में कंगना के साथ कलाकारों की एक शानदार मौजूदगी नजर आएगी, जिसमें गिरिजा ओक, स्मिता तंवे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेर्डे, आशा शेलार, सुहिला शेट्टे, रसिका अगाशे, आदित्य मिश्रा और जाहिर खान जैसे मझे हुए सितारे अहम भूमिकाओं में हैं।



मटका किंग के दूसरे सीजन का ऐलान, बृज भट्टी बनकर फिर लौटेंगे विजय वर्मा, नया पोस्टर भी रिलीज



विजय वर्मा इन दिनों अपनी हालिया रिलीज वेब सीरीज मटका किंग की सफलता का जश्न मना रहे हैं। यूं तो अभिनेता अपने नए-नए किरदारों से हमेशा दर्शकों का दिल जीतते आए हैं। सट्टा की दुनिया का बेताज बादशाह ब्रिज भट्टी का किरदार निभाकर उन्होंने

ओटीटी पर तहलका मचा दिया है। सीरीज को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद, आखिरकार निर्माताओं ने दूसरे सीजन की तैयारी शुरू कर दी है। इसका ऐलान उन्होंने एक पोस्टर के जरिए कर दिया है।

अमेजन प्राइम वीडियो ने मटका किंग 2 का ऐलान करते हुए लिखा, सीजन 2 के लिए तैयारियां

जोरों पर हैं। दूसरे सीजन पर काम जारी है। नागराज पोपटराव मंजुले द्वारा निर्देशित यह सीरीज बॉम्बे की 1960 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है। विजय ने इसमें कपास व्यापारी ब्रिज भट्टी का किरदार निभाया है, जो अपनी किस्मत को बदलने के लिए जुआ नेटवर्क को खड़ा करता है। सीरीज में कृतिका कामरा, सिद्धार्थ जाधव, साई ताहणकर और गुलशन प्रोवर भी हैं।

आपको बता दें कि 17 अप्रैल को मटका किंग का सीजन 1 प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। भारत समेत दुनिया भर के 240 देशों में इसे देखा जा रहा है।

रिलीज के बाद सिर्फ दो दिनों में ही यानि 17-19 अप्रैल के बीच इस सीरीज को 3।4 मिलियन व्यूवरशिप मिली। इसके बाद पहले हफ्ते में मटका किंग को रिकॉर्ड 4।5 मिलियन व्यूज मिले। ऑरिमेक्स मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 20-26 अप्रैल के बीच सबसे ज्यादा इस सीरीज को देखा गया। इसके बाद 27 अप्रैल से 3 मई के बीच इस सीरीज को 2।5 मिलियन व्यूज मिले।

'जलने वालों जलते...' शिल्पा शिंदे ने फिर पोस्ट की क्रिटिक वीडियो, उत्पीड़न विवाद के बीच ट्रोलर्स को दिया जवाब



भारती सिंह के पॉडकास्ट में यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने की बात को स्वीकार करने के बाद टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे सुर्खियों में आ गई हैं। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स और सेलेब्स उनको खरी-खोटी सुना रहे हैं। यह सब देखकर शिल्पा चुप नहीं बैठ रही हैं, उन्होंने टोलिंग करने वालों को क्रिटिक पोस्ट के जरिए अपना जवाब दिया है।

शनिवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट करते हुए शिल्पा शिंदे लिखती हैं, 'जलने वालों जलते रहो,

अपना खून किसी जरूरतमंद को मत दो, जला जला के खत्म कर दो।' इसके अलावा एक और फनी वीडियो पोस्ट वह शेयर करती हैं। इसमें एक रील उन्होंने बनाई है। इसमें वह एक फनी डायलॉग को बोल रही हैं, 'साफ साफ बोलने के चक्कर में, जिंदगी से लोग ही साफ हो गए।'

क्या था शिल्पा शिंदे का पूरा मामला?

टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने हाल ही में एक चौकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने भारती सिंह के पॉडकास्ट में बताया कि सीरियल 'भावोजी घर पर है' के प्रोड्यूसर संजय कोहली के खिलाफ झूठा यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। लेकिन बाद में मामला सुलझ गया था। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर शिल्पा की खूब ट्रोलिंग हुई, टीवी इंडस्ट्री से हिना खान भी उनके खिलाफ बातें कर रही हैं। कई लोगों को मानना है कि ऐसे झूठे केस की वजह से ही असल पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रान्त खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।

शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा।

RNI No: UPHIN/2014/57034

Website: aryavartkranti.com

*सम्पादक: प्रभात पांडेय

सम्पर्क: 9839909595, 8765295384

Email: aryavartkrantidainik@gmail.com